



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : जापान और थाईलैंड की मूल की अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर)।

फा. संख्या 15/29/2014-डीजीएडी : समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. उपरोक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान और थाईलैंड की मूल की अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के बारे में दिनांक 3 सितंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/31/2009-डीजीएडी द्वारा मूल जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 16 फरवरी, 2010 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करके अनन्तिम पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। सीमा-शुल्क की दिनांक 9 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 45/2010-सीमा-शुल्क द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाए गए थे। प्राधिकारी द्वारा 19 जनवरी, 2011 को अंतिम परिणाम की अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें जापान और थाईलैंड की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग

द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2011-सीमा-शुल्क द्वारा 9 अप्रैल, 2010 से 8 अप्रैल, 2015 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

2. मेसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे एचओसीएल भी कहा गया है) और मेसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे एसआई ग्रुप भी कहा गया है) ने दिनांक 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 36/2011-सीमा-शुल्क द्वारा थाईलैंड और जापान से फिनोल और एसीटोन के आयात पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की संयुक्त निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। याचिकादाताओं ने यह आरोप लगाया है कि जापान और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने है और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है तथा साथ ही उन्होंने संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की समीक्षा करने, उनको निरंतर जारी रखने तथा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के संबंध में पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर लागू रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इसकी जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/29/2015-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015-सीमा-शुल्क द्वारा शुल्क को 8 अप्रैल, 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नियमावली के नियम 17 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकारी द्वारा जांच को पूरा करने और अंतिम परिणाम की अधिसूचना जारी करने की समय-अवधि को 6 जुलाई, 2016 तक बढ़ा दिया था।

4. संबद्ध देशों के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, कोरिया जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपाई, संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर भी पाटन-रोधी शुल्क लागू हैं। वर्तमान समीक्षा जांच का कार्य-क्षेत्र, जापान और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू शुल्कों के संबंध में है और इसमें विगत जांच सभी पहलू शामिल हैं।

ख. क्रिया-विधि

5. इस जांच के संबंध में निम्नोक्त निर्धारित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (1) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित कर दिया गया है।
- (2) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां प्रदान कर दी हैं। आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति सार्वजनिक फाईल पर भी उपलब्ध करा दी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से जिसने भी अनुरोध किया है, उसे भी उसकी प्रति प्रदान कर दी गई है।

- (3) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों को (जिनके नाम और पते याचिकादाताओं द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई थीं और उन्हें नियमावली के नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया गया था:-

1. मेसर्ज पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल)
2. मेसर्ज चिब्रा फिनोल कंपनी लिमिटेड, शिओडोम
3. मेसर्ज मित्सुबिशी केमिकल्स
4. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड ("एमबीके"), जापान
5. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पसिफिक) प्राईवेट लिमिटेड, जापान (निर्यातक)
6. मेसर्ज मित्सुबिशी केमिकल कार्पोरेशन ("एमसीसी")
7. मेसर्ज सुनिटोमो कार्पोरेशन
8. मेसर्ज मित्सुई केमिकल्स इंक

- (4) संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (उत्पादक)
2. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान (निर्यातक)
3. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पसिफिक) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)

- (5) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां प्रेषित की गई थी और उन्हें सलाह दी गई थी कि वे पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार पत्र के जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें:-

1. मेसर्ज सीजे शाह एंड कंपनी
2. मेसर्ज हरेश कुमार एंड कंपनी, मुंबई
3. मेसर्ज पीसीएल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज
4. मेसर्ज कांतीलाल मणिलाल एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
5. मेसर्ज सोनकमल इंटरप्राइजिज, मुंबई
6. मेसर्ज खेतान ब्रोदर्स
7. मेसर्ज शुभव डाईज एंड केमिकल्स लिमिटेड
8. मेसर्ज एक्रान इंटरप्राइज
9. मेसर्ज नाईकनावरे केमिकल्स लिमिटेड
10. मेसर्ज पारस डाईज एंड केमिकल्स
11. मेसर्ज टोरेन्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुजरात

12. मेसर्ज यूनाईटेड फास्फोरस लिमिटेड, मुंबई
 13. मेसर्ज रेसिन्स एंड प्लास्टिक लिमिटेड
 14. मेसर्ज केलाश पोलिमर्स
 15. मेसर्ज सेंट्रम मेटेलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
 16. मेसर्ज वंडर लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
 17. मेसर्ज मेघदेव इंटरप्राइजिज
 18. मेसर्ज सतगुरू इंटरनेशनल
 19. मेसर्ज ब्लीच मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
 20. मेसर्ज कारमेन इंटरनेशनल (प्राईवेट) लिमिटेड
 21. मेसर्ज हाई पोलिमर्स लैब्स लिमिटेड
 22. मेसर्ज रेनबो कलर्स एंड केमिकल्स
 23. मेसर्ज कृष्णा एंटाओक्सिडेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
 24. मेसर्ज एनजीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 25. मेसर्ज फार्मसन फार्मास्युटिकल गुजरात लिमिटेड
 26. मेसर्ज इंडिया ग्लायकोल्स लिमिटेड
 27. मेसर्ज सिंघ प्लास्टिसाईजर्स एंड रेसिन्स (इंडिया) लिमिटेड
 28. मेसर्ज नेशनल प्लाईवोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 29. मेसर्ज कुन्दन राईस मिल्स लिमिटेड
- (6) संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा इस मामले में किसी प्रकार का कोई ठोस निवेदन नहीं किया है।
- (7) वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (18 महीनों) के लिए थी। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेष्य में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।
- (8) इस जांच में विश्लेषण के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- (9) संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ऐसे निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रदान की है, इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में नहीं माना गया है।

- (10) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध करा दिया था, ताकि नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनकी निरीक्षण किया जा सके।
- (11) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन-रोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम होता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने में पर्याप्त होगा।
- (12) प्राधिकारी ने 20 जनवरी, 2016 को हुई सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था। इस सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों/और उनके प्रत्युत्तरों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।
- (13) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान इस अंतिम जांच परिणाम में कर दिया गया है।
- (14) इस जांच के दौरान प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई ऐसी सूचना की प्रशिक्षता से स्वतः संतुष्ट हुए हैं, जिसके आधार पर ये परिणाम निकाले गए हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के परिसरों में जा कर जितना प्रासंगिक और आवश्यक हुआ है, स्वयं मौके पर जांच की है। घरेलू उद्योग से क्षति के बारे में अतिरिक्त अनुपूरक सूचना मांगी गई थी, जो उन्हें प्राप्त भी हो गई है।
- (15) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (16) नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के टिप्पणियों के लिए 17.06.2016 को मामले के सभी अत्यावश्यक तथ्यों से निहित प्रकटन विवरण जारी किया था। हितबद्ध पक्षकारों से उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों को जितना प्रासंगिक समझा गया है, इस परिणाम के उपयुक्त स्थानों पर उनका निदान कर दिया गया है।
- (17) इस परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की परिचायक है और प्राधिकारी ने इसे नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना है।
- (18) इस जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर, 1 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर = 60.76 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

6. दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 के मूल जांच के अंतिम परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:-

"विचाराधीन उत्पाद 'एसीटोन' है। एसीटोन एक आर्गेनिक रसायन है जो कि डिमिथिल केटोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग बल्क फार्मास्युटिकल्स, कृषि रसायन, रंजक पदार्थों, कुछ एक्सप्लोसिव्स और निचले स्तर के रसायनों में किया जाता है। एसीटोन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप-शीर्ष 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह एकल ग्रेड में विनिर्मित किया जाने वाला मूल आर्गेनिक रसायन है। यह बिना रंग का एक तरल पदार्थ है। इसका इस्तेमाल अनेक आर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है, जो कि विलायक या एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में होता है। विशेष रूप से एसीटोन का प्रयोग इसोफोरोन, डाईकेटोन, अल्कोहल, मिथिल मेथेक्रियलेट और बिसफिनोल 'ए' विनिर्मित करने के लिए किया जाता है। इनके अतिरिक्त इसका प्रयोग कुछ रबड़ रसायनों अथवा ओक्सी ऐसेथिलेने सेल्युलोज एसिटेट के लिए भी किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग एक विलायक के रूप में रंग-रोगनों/कोटिंग्स बनाने के लिए भी किया जाता है।"

7. याचिकादाताओं ने यह निवेदन किया है कि उनके द्वारा उत्पादित एसीटोन और संबद्ध देशों से आयातित एसीटोन वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यो और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान वस्तुएं ही हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग, एक दूसरे के स्थान पर करते हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप-शीर्ष 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र के संबंध में उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई प्रासंगिक निवेदन नहीं किया गया है। चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही रहेगा, जो कि मूल जांच में था।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिका मेसर्ज हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने फिनोल और एसीटोन के आयात पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। याचिकादाता भारत में फिनोल और एसीटोन के केवल उत्पादक हैं और इसलिए कुल भारतीय उत्पादन में उनका अंशदान होता है। जांच शुरू करने के चरण में याचिकादाताओं ने यह निवेदन किया था कि मेसर्ज एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध देशों सहित अनेक देशों से इन वस्तुओं के आयात किए थे। ऐसे आयात केवल केप्टिव खपत के लिए निशुल्क और शुल्क दत्त दोनों स्कीमों के अंतर्गत किए गए थे तथा आयातित वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा गया था। इस मामले में और जांच होने तक प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने के चरण में मेसर्ज एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड को एक घरेलू उद्योग के एक अंग के रूप में एक पात्र घरेलू उत्पादक माना था।

घ 1. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने निवेदनों में क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ मेसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखे जाने के प्रति कड़े तर्क दिए हैं और अन्य बातों के साथ-साथ उनके निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) विगत में एसआई ग्रुप द्वारा आयात किए जाने के कारण उसे घरेलू उद्योग से बाहर रखा गया है, जब कि उसने वर्तमान जांच अवधि के दौरान भी आयात किए हैं। यह निवेदन किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई अधिकतर मूल जांच में से अनेक जांच में एसआई ग्रुप को आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसलिए इस पाटन-रोधी जांच में एसआई ग्रुप की सहभागिता अत्यधिक असंगत रही है।
- (2) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन और की गई विक्रियों में एसआई ग्रुप का अधिक अंशदान है। एसआई ग्रुप ने आरोपित पाटन स्रोतों से आयात किए हैं और वह पाटन क्रियाकलापों में भाग ले कर स्वयं को बचाने के प्रयास से लाभान्वित हुआ है।
- (3) चाहे आयात केप्टिव खपत अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए किए गए हों, वे असंगत हैं, चूंकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप किए गए आयातों से भारत में वाणिज्यिक बाजार पर प्रभाव पड़ता है। जहां तक कि यदि एसआई ग्रुप ने अधिकतर आयातों का इस्तेमाल केप्टिव खपत के लिए किया है, तो भी उसने वाणिज्यिक विक्रियों के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और माल सूची से स्वयं को मुक्त रखा है। साथ ही उसने केप्टिव खपत को सस्ते पाटित आयातों से प्रतिस्थापित किया जाना भी सुनिश्चित किया है।
- (4) जब कि यह अविवादित है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे घरेलू उत्पादक को शामिल करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, जो कि आयातक भी हो, लेकिन ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग औचित्यपूर्ण और साम्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए तथ्यों की युक्तिसंगत और उद्देश्य पूर्ण जांच किए जाने के आधार पर ही एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- (5) विगत में अधिकतर मामलों में (जैसे कि चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “बांस के फाईबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाईबर” के आयातों से संबंधित जांच-2010, चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, कीनिया, ईरान, पाकिस्तान, यूकराईन और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित जांच-2012, चीन जनवादी गणराज्य, आस्ट्रेलिया, रूस और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “रबड अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लेक” के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर)-2013, इलेक्ट्रिकल इंसूलेटर्स-2015 आदि) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कुछ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। प्राधिकारी के सामने पेश आई इसी प्रकार की स्थितियों के पूर्व दृष्टांतों के आलोक में एक घरेलू उद्योग को बाहर रखने अथवा शामिल करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी को “घरेलू उद्योग” के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घरेलू उत्पादक को शामिल किए जाने के लिए जिन मुख्य प्राचलों की विशेष रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है, वे निम्नानुसार हैं:-

(क) उत्पादन और विक्रियों की तुलना में आयातों की मात्रा।

(ख) आयात के क्रियाकलापों के विरोध में घरेलू उत्पादन में उत्पादक द्वारा दर्शाई गई कटिबद्धता का स्तर अथवा दीर्घकालिक प्रकृति।

- (ग) यदि घरेलू उत्पादक को शामिल किए जाने से क्षति के परिणाम विकृत होते हैं, तो ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (6) प्राधिकारी के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए अभिज्ञात किए गए प्राचलों से एसआई ग्रुप के संबंध में उपरोक्त सूचना को अपने पास रखने से निम्नलिखित संबद्ध कारक सामने उभर कर आयेंगे:-
- (क) एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों का न केवल उत्पादन में ही बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्रियों में भी बड़ा अंशदान है।
- (ख) जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, उसके संबद्ध देशों से आयात, पाटन-रोधी शुल्कों/सतत जांच के अध्यक्षीन हैं, जो कि एसआई ग्रुप के कुल उत्पादन का 37% से भी अधिक हैं।
- (ग) इसलिए यह अविवादित है कि एसआई ग्रुप ने न केवल आरोपित पाटन स्रोतों से आयात किए हैं, बल्कि वह आरोपित पाटन से लाभान्वित भी हुआ है और इस प्रक्रिया में उसने पाटन क्रियाकलापों के विरोध में भाग ले कर स्वयं को बचाया भी है।
- (घ) एसआई ग्रुप के वर्तमान क्रियाकलाप एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के निरंतर जारी रहना मात्र है, जैसा कि प्राधिकारी ने की गई विगत जांच में भी माना है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि एसआई ग्रुप की आरोपित पाटन स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के प्रति दीर्घकालिक कटिबद्धता है।
- (7) प्राधिकारी एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों को पृथक करके शुल्क दत्त आयात और निशुल्क आयात दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं और उसके प्रचालनों और मार्जिन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं तथा उसे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि वे इस संबंध में सार्थक निवेदन कर सकें।
- (8) उपरोक्त स्थितियों के आलोक में प्राधिकारी को अपने पास उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत दिए गए व्यापक विवेकाधिकार का यथोचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए तथा क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ एस आई ग्रुप को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए।

घ 2. याचिकादाताओं के विचार

12. याचिकादाताओं ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि वर्तमान जांच में मेसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड नामक याचिकादाता देश में विचाराधीन उत्पाद के अकेले उत्पादक हैं। हालांकि मेसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं लेकिन ये आयात संबद्ध देशों से नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे आयात निचले स्तर के उत्पादों का निर्यात उत्पादन करने के लिए शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं। कंपनी ने व्यापारिक प्रयोजनार्थ ऐसे आयात नहीं किए हैं और इसलिए उसका ऐसा कार्य को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि एसआई ग्रुप के आयात गैर-संबद्ध देशों से संबंधित हैं, इसलिए वे वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

13. इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एसीटोन और फिनोल के विभिन्न मामलों में यह निर्णय दिया है कि चाहे आयात केप्टिव खपत के लिए किए गए हों अथवा वाणिज्यिक बिक्रियों के लिए किए गए हों, यह एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। तथापि, उपरोक्त तथ्य के बावजूद प्राधिकारी एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रख सकते हैं और केवल से संबंधित आंकड़ों/सूचना पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं।

ष 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तर्कों के आलोक में क्षति की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्स एसआई ग्रुप की पात्रता के मुद्दे की नियमावली और विधिशास्त्र के अनुसार जांच की है।

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप और एचओसीएल ने संयुक्त निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें दोनों उत्पादों को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किया गया है तथा इन दोनों उत्पादों के लिए लिप्त देश और जांच की अवधि समान है। जांच के समय एसआई ग्रुप ने यह दावा किया है कि उन्होंने प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत कुछ मात्रा में फिनोल के आयात किए थे और कुछ मात्राओं के आयात विभिन्न देशों से किए गए थे जिनमें जांच अधीन कुछ देश भी शामिल हैं, जो कि निचले स्तर के उत्पादों के केप्टिव उत्पादन के लिए लागू शुल्कों का भुगतान करके किए गए थे। कंपनी ने आगे यह भी घोषणा की है कि उन्होंने शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत एसीटोन की कुछ मात्रा में आयात, निर्यात संसाधन के लिए भी किए थे। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि उन्होंने किसी भी आयातित वस्तु को घरेलू बाजार में नहीं बेचा है। इन घोषणाओं के आधार पर एसआई ग्रुप को इस मुद्दे में और जांच-पड़ताल किए जाने तक, जांच की शुरुआत करने के समय घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र में शामिल किया गया था।

16. जांच के दौरान यह पाया गया है कि जांच अवधि के दौरान एसआई ग्रुप ने फिनोल की 12246.43 मी.टन मात्रा के आयात किए थे जिसमें से 7455.732 मी.टन के आयात निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत किए गए थे और 4745.346 मी.टन की शेष मात्रा के आयात शुल्क का भुगतान करके किए गए थे। शुल्क का भुगतान करके किए गए आयातों में से 45.35 मी.टन की मात्रा घरेलू बाजार में बेची गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया है कि ऐसे सभी आयात थाईलैंड से किए गए थे जो कि इस मामले में जांच अधीन एक देश है। जांच अवधि के दौरान इस कंपनी के आयातों में से लगभग 23 प्रतिशत फिनोल के उसके निजी उत्पादन के लिए हैं। इसी प्रकार एसआई ग्रुप ने निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत एसीटोन की 9924 मी.टन मात्रा के आयात किए थे। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया है कि एसीटोन के सभी आयात जांच अधीन देशों से किए गए हैं। जांच अवधि के दौरान लगभग 30 प्रतिशत आयात उसके निजी उत्पादन के लिए किए गए हैं।

17. इसके साथ ही प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कंपनी ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि चूंकि एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयात, गैर-संबद्ध देशों से संबंधित हैं, इसलिए वे वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। याचिकादाताओं द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया है कि एसआई ग्रुप ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं के आयात नहीं किए थे और इसलिए उनके ऐसे कार्य को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं मानना चाहिए, हालांकि इस कंपनी द्वारा आयातित फिनोल की लगभग 45 मी.टन की मात्रा के लिए शुल्क अदा किया गया था और जिसे जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचा गया था। जांच करने से यह भी पता चला है कि एसआई ग्रुप ने इन दो जांच की जांच अवधि के पश्चात फिनोल और एसीटोन दोनों की पर्याप्त मात्रा में निरंतर आयात करना जारी रखा है। कंपनी के विगत इतिहास से भी ऐसा पता चलता है कि वे अपनी निजी खपत के लिए वस्तुओं का निरंतर आयात करते रहे हैं।

18. मामले की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नियमावली के अंतर्गत दी गई घरेलू उद्योग की परिभाषा और उनके लिए उपलब्ध विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक

आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता घरेलू उत्पादकों में से एसआई ग्रुप नामक एक घरेलू उत्पादक ने निर्यात उत्पादन के लिए अधिकतर अपनी निजी केप्टिव खपत के लिए फिनोल और एसीटोन दोनों के आयात किए हैं। पूर्व जांच में भी प्राधिकारी के समक्ष यह तथ्य मौजूद था और इस कंपनी को कुछ मामलों में घरेलू उद्योग में शामिल किया गया था और कुछ अन्य मामलों में इस कंपनी को उन मामलों के वास्तविक सांचे से बाहर रखा गया था। अन्य जांच प्राधिकारियों के लिए निहित विधि और विधिशास्त्र का अब यह प्रमाणिक तथ्य है कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 4.1 तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे उत्पादकों को जिन्होंने स्वयं पाटित उत्पादों के आयात किए हैं, स्वतः बाहर रखा जाए, लेकिन ऐसे मामले में प्राधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वे अलग-अलग मामले के आधार पर इसकी जांच करें कि क्या ऐसी स्थिति में किसी उत्पादक को शामिल करने अथवा बाहर रखने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से घरेलू उत्पादक को बाहर रखे जाने का निर्णय लेते समय प्राधिकारियों को सामान्यतया निम्नलिखित कारकों की जांच करनी अपेक्षित होती है:-

- क्या उसके निजी उत्पादन और बिक्री की तुलना में आयात छुट-पुट और कम हुए हैं, जो कि नियमित घटना नहीं है।
- क्या कुछ स्थितियों से निपटने के लिए आयात करने आवश्यक हैं, जैसे कि उत्पादन के मुद्दे अथवा ये ऐसे ग्रेडों के संपूरक हैं जो कि उसके द्वारा विनिर्मित नहीं किए जाते हैं अथवा गुणवत्ता परीक्षण और उत्पाद विकास आदि के लिए हैं।
- उनकी उत्पाद श्रृंखला को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता है, ताकि वे मांग को पूरा कर सकें।
- क्या घरेलू उद्योग के रूप में परिभाषित किए जाने के लिए कोई अन्य सक्षम घरेलू उत्पादक नहीं है।

20. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी के पास उपलब्ध विवेकाधिकार का विगत में भी ऐसी परिस्थितियों में प्रयोग किया गया है, जिनमें शिकायतकर्ता उत्पादक एक मात्र घरेलू उत्पादक है अथवा उनके उत्पादन की तुलना में उनके आयात बहुत महत्व नहीं रखते हैं तथा बिक्री और/या आयात, उत्पाद विकास और परीक्षण आदि के लिए किए जाते हैं। मौजूदा मामले में एसआई ग्रुप अत्यधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के आयात कर रहा है, हालांकि उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वस्तुओं के प्रमुख भाग का उपयोग निर्यात बिक्रियों के लिए उनके निचले स्तर के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयातों की छोटी मात्रा को घरेलू बाजार में बेचा गया है और यह तथ्य जांच शुरू करने के समय प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में सरकारी क्षेत्र में मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स (एचओसीएल) नामक केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसके पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं। लेकिन मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स (एचओसीएल) की उत्पादन सुविधाएं अक्सर चालू और बंद रहती हैं और उसने जांच अवधि के दौरान कुछ अन्य कारकों के कारण केवल कुछ महीनों के लिए प्रचालन कार्य किया है, हालांकि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अनेक कारकों के कारण इस उत्पादक का उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से लंबे समय तक पाटन का निरंतर जारी रहना शामिल है, जिसके फलस्वरूप जांच अवधि के दौरान उनका संयंत्र काफी लंबे समय तक बंद पड़ा रहा। ऐसी स्थिति में यदि एसआई ग्रुप को क्षति की जांच करने के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तो क्षति का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहारिक रूप से कोई अर्थक्षम घरेलू उद्योग विद्यमान नहीं होगा और क्षति जांच अत्यधिक विषम हो जाएगी अथवा संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव या संभावित प्रभाव का उचित विश्लेषण करना संभव नहीं होगा।

21. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी विधिवत् सावधानी पूर्वक नियम 2 (ख) के अंतर्गत उनके पास उपलब्ध विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं और एसआई ग्रुप को इस मामले में क्षति की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में मानते हैं।

22. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदन में यह टिप्पणी की है कि प्राधिकारी ने यह निर्णय लेने के लिए कि क्या एक घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाए, अनेक कारकों की जांच करके सही दिशा में कदम उठाया है। तथापि, उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के बावजूद भी प्राधिकारी ने विधिवत् सावधानी पूर्वक नियम 2 (ख) के अंतर्गत उनके पास उपलब्ध विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और एसआई ग्रुप को मात्र इस कारण से घरेलू उद्योग मानने का निर्णय लिया है कि यदि एसआई ग्रुप को क्षति की जांच करने के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तो क्षति का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहारिक रूप से कोई अर्थक्षम घरेलू उद्योग विद्यमान नहीं होगा और क्षति जांच अत्यधिक विषम हो जाएगी अथवा संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव या संभावित प्रभाव का उचित विश्लेषण करना संभव नहीं होगा। इससे एक खतरनाक पूर्व निर्णय स्थापित हो सकता है जिससे भारतीय विनिर्माता संबद्ध वस्तुओं के आयात करने और ऐसे आयातों से लाभान्वित होने के बावजूद घरेलू उद्योग के रूप में योग्य पात्र बनने का सदैव एक तरीका प्राप्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों से भारत में घरेलू बाजार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, हालांकि उन्होंने उनका अधिकतर उपयोग निचले स्तर के निर्यातों के लिए किया है। इसके अतिरिक्त एसआईग्रुप इन आयातों से प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुआ है, चूंकि वह निर्यात बाजार में अपने निचले स्तर के उत्पाद को प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर बेचने में सक्षम हुआ है।

23. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है और मामले के वास्तविक सांचे में यह आवश्यक पाया गया है कि इस मामले में क्षति की जांच करने के लिए एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में बनाए रखा जाए।

ड. इस जांच में हितबद्ध पक्षकार

24. जैसा कि उपरोक्त पैरा 5 (4) और (5) में निर्दिष्ट किया गया है, याचिकादाताओं के अतिरिक्त उन प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों को हितबद्ध पक्षकार माना गया है, जिन्होंने इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में स्वयं को परिचित कराया है। साथ ही प्रतिवादी देशों की सरकारों को भी इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।

च. विविध मुद्दे

च1. गोपनीयता

25. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि याचिकादाताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमतों के समायोजन का आधार प्रस्तुत नहीं किया और लागत संबंधी सूचना के लिए सूचीबद्ध श्रृंखलाएं प्रपत्र क, ख, ग-1, ग-2, घ और ङ में प्रस्तुत नहीं की हैं तथा याचिका में कम बिक्री मार्जिन, नियोजित पूंजी और क्षतिरहित कीमत का प्रकटन, उसके संक्षिप्त रूप में अथवा सूचीबद्ध श्रृंखलाओं में नहीं किया है।

26. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग के गोपनीयता के सभी दावे कानूनी प्रावधानों, डीजीएडी द्वारा जारी किए गए व्यापारिक नोटिस तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर, अत्यधिक गोपनीय हैं और ये घरेलू उद्योग को उन पर उचित टिप्पणियां करने के लिए रोकते हैं।

27. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जितना संभव और व्यवहारिक हो सका है, सूचना प्रस्तुत करने वाले विभिन्न पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की गई है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति के आधार पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है। जहां तक निर्यातकों के निवेदनों का संबंध है, जितना संभव हो सका है, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई उसी सूचना को सार्वजनिक फाईल पर रखा गया है, जो कि उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के व्यवसाय के प्रति संवेदी नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी पक्षकारों के गोपनीयता के दावों के संबंध में सभी पक्षकारों की आपत्तियों का निदान कर दिया गया है।

च 2. अन्य मुद्दे

28. प्रतिवादी पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकादाताओं द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत की याचिका इस हद तक कमजोर है कि यह संभावना का पर्याप्त रूप से निदान नहीं करती है और यह अपने दावों को संपुष्ट करने में बिना किसी प्रमाण के निराधार आरोप लगाती है। वास्तव में संभावना के दावे के संबंध में याचिकादाता स्वयं का खंडन करते हुए प्रतीत होते हैं। याचिकादाताओं ने याचिका में ऐसा दावा किया है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोई सुधार दृष्टिगत नहीं हुआ है। उसी पैरा में याचिकादाताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि निम्न स्तर पर निरंतर पाटन हो रहा है। ऐसी भ्रामक विवरणों का उद्देश्य हितबद्ध पक्षकारों और निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रम में डालना है। इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

29. इसके अतिरिक्त जहां तक जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का संबंध है, याचिकादाताओं ने अपनी निजी याचिका में सीधे स्वयं का खंडन किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि और विगत वर्ष के दौरान जापान से संबद्ध वस्तुओं के कोई आयात नहीं हुआ है।

30. यह निवेदन किया गया है कि प्राधिकारी ने अनेक जांच में ऐसी वास्तविक स्थिति की जांच की है, जिसमें हाल ही के वर्षों में संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं किए गए थे और ऐसे मामलों में शुल्कों को समाप्त कर दिया था। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि (1) जापान से एसीटोन के कोई आयात नहीं किए गए हैं, (2) थाईलैंड से एसीटोन के आयातों में तेजी से गिरावट आई है तथा (3) जांच अवधि के दौरान एसआई ग्रुप एसीटोन का प्रमुख आयातक है, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखे जाने का कोई कारण नहीं है।

31. निर्यातकों ने अपने निवेदनों में यह तर्क भी दिया है कि याचिकादाता स्वभाविक रूप से अकुशल हैं और उन्होंने अपनी प्रचालनात्मक कमियों और पीछे हटने के कारण स्वयं को क्षति पहुंचाई है तथा दशकों से पाटन-रोधी उपायों पर निरंतर विश्वास किया है। यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 1987 में उसके संयंत्र की अवस्थापना से ही एचओसीएल अपनी उत्पादन सुविधाओं अथवा प्रक्रिया में कोई सुधार करने में विफल रहा है, जबकि वर्ष 1999 से देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 से एचओसीएल को एक रूग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हाल ही में अंतराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के कारण एचओसीएल के अपरिष्कृत फिनोल के विनिर्माण संयंत्र को बंद करना पड़ा है तथा एचओसीएल ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि कच्चे माल की कमी के फलस्वरूप उसे अपने संयंत्र का बंद करना पड़ा है, जिसका संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन से कोई सह-संबंध है। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की घोर कमी होने के फलस्वरूप भी उसे उत्पादन बंद करना पड़ा है।

32. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने का उद्देश्य और महत्व यह है कि घरेलू उद्योग को उचित कीमतों पर अपनी सामग्री को बेचने के लिए बाजार में उचित व्यापक अवसर प्राप्त हो सकें। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से बाजार में उचित अवसर प्राप्त

नहीं हुए हैं। तथापि, पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप शुल्क को निरंतर जारी रखने अथवा शुल्क की पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने लगेगी।

33. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात यह निवेदन किया है कि पाटन-रोधी शुल्कों के इतिहास पर उचित विचार करने से वर्तमान जांच की महत्ता का पर्याप्त रूप से विश्लेषण जा सकता है। प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात विवरण में इस तथ्य को ध्यान में रखा है। यह तर्क दिया गया है कि एक दशक से घरेलू उद्योग द्वारा पाटन-रोधी शुल्कों पर बार-बार इसलिए विश्वास किया गया है, ताकि वह अपनी अकुशलता को छिपा सके और उसने घरेलू बाजार से सभी प्रतिस्पर्द्धा को सुव्यवस्थित ढंग से समाप्त करने का प्रयास किया है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की पाटन-रोधी जांच किए जाने का लंबा इतिहास रहा है तथा वर्ष 2002 से विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाए गए हैं। संबद्ध देशों के अतिरिक्त इस समय ऐसे शुल्क चीनी तार्ईपाई, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन, कोरिया जनवादी गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, सऊदीअरब और सिंगापुर से आयातों पर लगाए गए हैं।

35. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में कि याचिकादाता स्वभाविक रूप से अकुशल होने के कारण पाटन-रोधी शुल्क से निरंतर संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी की ऐसी सुसंगत प्रथा रही है कि वे शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने पर पाटन और क्षति होने की संभावना सहित मूल जांच के सभी पहलुओं की समीक्षा करें। तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की उस सीमा तक जितना प्रासंगिक था और उनके समर्थन में प्रमाण उपलब्ध थे, उचित जांच की गई है।

36. पाटन और क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी अन्य मुद्दों का निदान, उस सीमा तक जितना प्रासंगिक था और उनके समर्थन में प्रमाण उपलब्ध थे, इस परिणाम में संबंधित भागों में कर दिया गया है।

ख. वर्तमान पाटन का निर्धारण करने की कार्यप्रणाली

ख 1. कानूनी स्थिति

37. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 क (5) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

“इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटन-रोधी शुल्क, यदि पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तो ऐसा शुल्क उसको लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा;

बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार का उसकी समीक्षा करने पर ऐसा विचार बनता है कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के निरंतर होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर इसकी अवधि को आगे पांच वर्ष तक बढ़ा सकती है और आगे बढ़ाई गई ऐसी अवधि, ऐसा विस्तार करने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

बशर्ते कि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले शुरू की गई ऐसी समीक्षा का निष्कर्ष, ऐसी समाप्ति से पहले नहीं निकाला गया है, तो उस स्थिति में ऐसी समीक्षा के निष्कर्ष निकाले जाने तक पाटनरोधी शुल्क निरंतर जारी रहेगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

38. तदनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को निम्नोक्त की जांच करनी अपेक्षित होती है:-

- क्या पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने के बाद पाटन निरंतर जारी रहता है और यदि हां, तो क्या उसके निरंतर जारी रहने की संभावना है।

- ऐसे मामलों में जिनमें पाटन निरंतर जारी नहीं रहा है, पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्या पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- क्या घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी और यदि हां, तो पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्या घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति के निरंतर होते रहने की संभावना है।
- ऐसे मामलों में जिनमें घरेलू उद्योग को निरंतर ऐसी क्षति नहीं हुई है, पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्या घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

39. इसलिए प्राधिकारी ने इसकी जांच करने से पहले कि क्या ऐसे पाटन आयातों से घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी और ऐसी स्थिति में उसके निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इसकी जांच करने की कार्यवाही की है कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है और पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्या ऐसे पाटन के निरंतर होते रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ 2. निरंतर पाटन होने की जांच: सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड और जापान के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (उत्पादक)
2. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान (निर्यातक)
3. मेसर्ज मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)

41. सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य सूचना के आधार पर इन दोनों देशों से संबद्ध वस्तुओं के वर्तमान पाटन और उसके निरंतर बने रहने की संभावना अथवा पाटन की पुनरावृत्ति होने की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

थाईलैंड

42. डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार जिस पर विश्वास किया गया है, जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से एसीटोन की 3880 मी.टन मात्राके आयात किए गए थे। थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी, मेसर्ज पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (पीपीसीएल) ने इस मामले में अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इस निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इस अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के {***} मी.टन निर्यात किए थे। यह प्रत्यक्ष अंतर इस कारणवश था कि विगत अवधि के एक कारोबार को जांच अवधि में क्लीयर किया गया था।

43. जांच अवधि के दौरान पीपीसीएल ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के सीधे निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए थे। मौके पर जांच करके उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को सत्यापित किया गया है। तदनुसार उत्पादन करने वाले इस निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

सामान्य मूल्य

44. जांच अवधि के दौरान पीपीसीएल ने घरेलू बाजार में {***} कि.ग्रा संबद्ध वस्तुओं को बेचा था। तथापि, उसने केवल {***} कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया था और {***} कारोबार की तुलना में उन्हें बेचा था जबकि शेष व्यापार विक्रियां थीं। घरेलू विक्रियां नियमित क्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित संविदाओं के आधार पर हैं

और कीमतों का निर्धारण, आसीआईएस एलओआर दक्षिण-पूर्व एशिया कीमत से जुड़े फार्मूले से किया जाता है। जांच अवधि के दौरान पीपीसीएल ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुएं बेची थीं। घरेलू आपूर्तियां एक्स-टैंक की हैं अथवा उनकी सुपुर्दगी विभिन्न क्रेडिट/भुगतान शर्तों पर की जाती है। कंपनी ने घरेलू बिक्री कीमतों का समायोजन करने के लिए इन व्ययों के ब्यौरे प्रदान किए थे।

45. यह नोट किया गया था कि हालांकि घरेलू बिक्रियां, समस्त जांच अवधि के दौरान की गई हैं, लेकिन निर्यात बिक्रियां जांच अवधि में केवल कुछ महीनों के लिए की गई हैं। विश्व बाजार में मूल कच्चे माल नामतः ब्रेनेजीन और प्रोपलीन की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण उत्पादक ने मासिक आधार पर सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमत का निर्धारण करने का अनुरोध किया है और उसने एसीटोन की मास-वार लागत शीट प्रदान की है। तदनुसार मासिक-वार घरेलू बिक्रियों को व्यापारिक जांच की सामान्य प्रक्रिया के अध्यधीन रखा गया था और मासिक सामान्य मूल्य का निर्धारण, अंतर-देशीय भाड़े, हैंडलिंग व्ययों और जहां कहीं भी लागू होता है, क्रेडिट लागत के लिए होने वाले व्यय के लिए घरेलू बिक्रियों का समायोजन करने के बाद किया गया है, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

46. जांच अवधि के दौरान पीपीसीएल ने {***} कि.ग्रा संबद्ध वस्तुओं के सीधे निर्यात भारत में स्वतंत्र क्रेताओं को किए हैं। ऐसी सभी बिक्रियां एफओबी शर्तों पर तथा 90 दिनों के क्रेडिट पर की गई थीं। उत्पादन करने वाले निर्यातक ने हैंडलिंग व्ययों के लिए व्यय संबंधी सूचना प्रदान की है, जिसमें भंडारण लागत, थ्रू पुट लागत, लदान लागत और पर्यवेक्षक का शुल्क तथा क्रेडिट व्यय शामिल हैं, जिनका सत्यापन किया गया था।

47. एसीटोन की पहले सुपुर्दगी, थाई टैंक टर्मिनल को वितरण करने के लिए की गई थी जो कि घरेलू और बल्क में निर्यात दोनों के लिए थी। कंपनी थाई टैंक टर्मिनल को नियत शुल्क और थ्रू पुट शुल्क का भुगतान करती है। तदनुसार पीपीसीएल ने हैंडलिंग व्यय के दावे किए हैं जिनमें भंडारण और थ्रू पुट व्यय शामिल हैं। कंपनी के निर्यातों के लिए निबल कार्यगत निर्यात कीमत का निर्धारण, अंतर-देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, हैंडलिंग व्ययों, जहां कहीं भी लागू होता है, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार का उचित समायोजन करने के बाद किया गया है, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। निर्यात बल्क रूप में हैं और उनमें कोई पैकिंग व्यय नहीं होते हैं। तदनुसार मासिक-वार निबल कार्यगत निर्यात कीमत का आकलन किया गया है, जो कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

48. कार्यगत स्तर पर निर्धारित मासिक-वार सामान्य मूल्य की तुलना मासिक-वार निर्यात कीमत से की गई है, ताकि पीपीसीएल के लिए पाटन मार्जिन का आकलन किया जा सके, जो कि निम्नानुसार है:-

रो लेबिल्स	मात्रा का योग कि.ग्रा.	निबल मूल्य अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन का %
मई -13	***	***	***	***	
अगस्त - 13	***	***	***	***	
नवंबर - 13	***	***	***	***	
कुल योग	***	***	***	***	5-15%

थाईलैंड से सभी अन्य निर्यातक

49. थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं का कोई और अन्य उत्पादक नहीं है। इसलिए थाईलैंड में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए शेष पाटन मार्जिन का निर्धारण करना निष्फल है और इसलिए ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है।

जापान

50. विश्वास किए गए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान जापान से कोई आयात नहीं किया गया है। जापान में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए जापान के संबंध में पाटन मार्जिन का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

51. उपरोक्त जांच से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक था और उक्त अवधि के दौरान जापान से कोई पाटन नहीं हुआ था।

ज. पाटन के निरंतर रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना**ज 1. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

52. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने निवेदनों में दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाताओं ने कुछ अस्पष्ट और अप्रमाणित पाटन मार्जिन परिकलित किए हैं।
- (2) याचिकादाताओं ने निर्यात अभिमुखीकरण को अधिप्रमाणित करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वे इस संबंध में तृतीय देश के आंकड़ों के स्रोत और प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
- (3) कीमत के आकर्षक होने का तर्क इस कारण से खंडनात्मक है कि याचिकादाता के आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि भारत में वर्तमान निर्यात कीमत से लागत भी वसूल नहीं होती है। याचिकादाताओं का तर्क उत्पादक की साम्यता की अवधारणा का खंडन करता है। वे ऐसा दर्शा रहे हैं कि लागत से कम बिक्री "आकर्षक" है।
- (4) जांच अवधि में कीमत में कटौती निरंतर स्थिर बनी हुई है। फिर भी क्षति की मात्रा और लाभप्रदता में मूलभूत अंतर देखा गया है, जिससे पता चलता है कि कीमत में कटौती का घरेलू उद्योग को हुई क्षति से कोई सह-संबंध नहीं है।

ज 2. घरेलू उद्योग के विचार

53. घरेलू उद्योग द्वारा अपने निवेदनों में दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं:-

- (1) थाईलैंड के मामले में पाटन निरंतर बना हुआ है। थाईलैंड के मामले में आयातों की मात्रा अत्यधिक है जिससे पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना के संबंध में निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- (2) जापान के मामले में हालांकि वर्तमान जांच अवधि में कोई आयात नहीं किया गया है, फिर भी पाटन कीमतों पर तृतीय देशों को अत्यधिक निर्यातों से पाटन और क्षति की संभावना का स्पष्ट पता चलता है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (3) जापान से तृतीय देशों को अत्यधिक निर्यात किए गए हैं, जिससे अत्यधिक क्षति मार्जिन का पता चलता है। इसके साथ ही थाईलैंड से भी तृतीय देशों में अत्यधिक पाटन हुआ है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारत में तृतीय देशों के आयातों से पाटन होने की प्रबल संभावना है।
- (4) विगत जांच में और वर्तमान याचिका में निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक है और इससे स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और उससे परिणामी क्षति होने की संभावना है।

- (5) जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे उस कीमत से काफी कम हैं, जिस पर संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।
- (6) कीमत में काफी अधिक कटौती हो रही है, जिसके शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने पर और गहन होने की संभावना है। जापान के निर्यातकों द्वारा जांच अवधि में तृतीय देशों को विचाराधीन उत्पाद के किए गए निर्यातों की कीमत को ध्यान में रखते हुए जापान की निर्यात कीमत से कीमतों में अत्यधिक कटौती होने की संभावना है।
- (7) संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का पाटन, अन्य पाटन स्रोतों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति, पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, सभी विभिन्न प्राचल हैं और उन पर तदनुसार विचार किया जाना चाहिए।
- (8) अतिरिक्त क्षमता संभावना का निर्धारण करने के लिए प्रमाणित प्राचल है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की अधिक संभावना है।
- (9) देश में अतिरिक्त क्षमता होने के फलस्वरूप गृह देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि उत्पाद की कीमतों में गिरावट आना, लाभप्रदता का कम होना, कोर्पोरेट-क्षेत्र में संकट और वित्तीय क्षेत्र में संकट आना जिसके कारण उत्पादक प्रयोज्य कीमतों पर देश से बाहर अवसर की तलाश करने लगता है। नागरिकों की क्रय शक्ति उसी दर से नहीं बढ़ सकती है। चूंकि मांग पहले से ही अधिक होती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में निवेशों पर नियंत्रित रखना होता है क्योंकि निवेश करने से लाभ होने के बजाय हानि होने लगती है। क्षमता में संवृद्धि, पाटन-रोधी जांच में संभावित विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है।
- (10) यह आवश्यक नहीं है कि घाटों में वृद्धि होने से कीमत में कटौती बढ़ने लगती है। ये दोनों प्राचल भिन्न हैं।

ज 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

54. विगत भाग में यह उल्लेख किया गया था कि जांच अवधि के दौरान जापान से कोई पाटित आयात नहीं हुए थे। थाईलैंड से पाटित कीमतों पर आयात हुए थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा में यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या थाईलैंड से पाटन जारी रहेगा अथवा यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या जापान से इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस संबंध में प्राधिकारी ने कीमत के चलन और संबद्ध देशों में प्रमुख उत्पादकों की क्षमताओं की जांच की है।

55. जहां तक थाईलैंड का संबंध है, थाईलैंड में पीपीसीएल एसीटोन का केवल अकेला प्रमुख उत्पादक है, जिसकी अधिकतम क्षमता लगभग {***} केटी प्रति वर्ष है, जिसका वे प्रचालन 100% क्षमता उपयोग से अधिक स्तर पर करते हैं। कंपनी ने यह निवेदन किया है कि थाईलैंड में एसीटोन की खपत मुख्यतया बीपीए और एमएमए उत्पादन के लिए की जाती है और इसकी वार्षिक मांग लगभग 160,000 मी.टन है। चूंकि वर्ष 2010 से उन्होंने अपने निजी बिस-फिनोल ए (बीपीए) का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, इसलिए एसीटोन के उनके निर्यात काफी कम हो गए हैं। वर्ष 2013 में उनके द्वारा एमएमए का उत्पादन शुरू करने के बाद से निर्यात की मात्रा और घट गई है। पीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि उनकी घरेलू बिक्रियां और केप्टिव खपत, क्षति की जांच अवधि में वार्षिकीकृत आधार पर उनके वार्षिक उत्पादन का लगभग (***) % बनती है। उनके निर्यात जो कि उत्पादन के लगभग (***) % बनते थे, जांच अवधि में घट कर (***) % रह गए हैं, जिससे पता चलता है कि वस्तुओं की घरेलू खपत में वृद्धि हुई है।

56. पीपीसीएल ने अपने उत्तर में यह बताया है कि वे घरेलू बाजार और तृतीय देशों से प्रमुख मांग को पूरा करने के प्रयोजन से फिनोल की क्षमता को दुगुना करने के लिए निकट भविष्य में अपनी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एसीटोन की उनकी क्षमता भी उसी अनुपात से बढ़ जाएगी। कंपनी ने यह सूचित किया है कि वह घरेलू और तृतीय देशों के ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। इसलिए जब कि घरेलू खपत में वृद्धि होने से कंपनी के निर्यात अभिमुखीकरण में उत्तरोत्तर कमी हो रही है, फिर भी ऐसा पता चलता है कि पीपीसीएल के निकट भविष्य में विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक निर्यात होते रहेंगे।

57. जांच अवधि के दौरान पीपीसीएल की कीमत प्रवृत्ति से ऐसा पता चलता है कि घरेलू बाजार और तृतीय देशों में कीमतें संकुचित बैंड में थीं। सकल स्तर पर निर्यात कीमतें, घरेलू कीमतों से मामूली अधिक थीं। हालांकि सकल स्तर पर कीमतों से पाटन के वास्तविक स्तर का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, फिर भी ये विशेष रूप से अधिक नहीं होंगी। इसलिए घरेलू उद्योग का यह तर्क कि थाईलैंड से तृतीय देशों के निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं और इसलिए यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो भारत में पाटन के गहन होने की संभावना है, इन तथ्यों से सिद्ध होना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में जांच पश्चात अवधि (अक्टूबर 2014 – मार्च, 2015) के आंकड़ों की भी जांच की गई है और इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस तथ्य के बावजूद कि एचओसीएल ने उत्पादन करना पूर्णतया बंद कर दिया है और लगभग 20,000 मी.टन के अतिरिक्त अंतर की पूर्ति बड़े हुए आयातों से की जानी है, थाईलैंड से एसीटोन के आयातों की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। कीमत के क्षेत्र में समस्त देशों की कीमतों से वर्ष 2015 की प्रथम तिमाही से विशेष गिरावट आने का पता चलता है, जिसका प्रत्यक्ष कारण अपरिष्कृत कीमत स्थिति है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तब भी थाईलैंड से आयात वर्तमान स्तर पर निरंतर जारी रहेंगे। चूंकि थाईलैंड की कीमतें वैश्विक प्रवृत्ति का अनुसरण कर रही हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विश्व के अन्य उत्पादकों की तुलना में इस उत्पादक द्वारा निकट भविष्य कीमतों में प्रमुख कटौती की जाएगी।

58. जापान के संबंध में उल्लेखनीय है कि जांच अवधि के दौरान इस देश से एसीटोन का कोई आयात नहीं हुआ है। क्षति की जांच अवधि के दौरान वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में विशेष आयात हुए थे। जापान में किसी भी उत्पादक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जापान में संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख उत्पादक, मित्सुई एंड कंपनी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं जिसमें उसने जापान में उत्पादन और घरेलू खपत के आंकड़े प्रदान किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जापान का एसीटोन का कुल उत्पादन, वर्ष 2013 में 500 केटी से घट कर लगभग 375 केटी रह गया है, जिसका प्रत्यक्ष कारण कोसन में इडेमिट्सु के साथ मित्सुई केमिकल्स के संयुक्त उद्यम संयंत्र का सितंबर, 2014 में बंद हो जाना है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार देश में मांग, जो कि उसके उत्पादन की तुलना में अत्यधिक कम थी, घरेलू उत्पादन के समतुल्य हो जाएगी जिससे देश में विशेष रूप से अतिरिक्त उत्पादन नहीं होने का पता चलता है।

59. मित्सुई द्वारा सूचित किए गए कीमत स्तर से पता चलता है कि सकल स्तर पर घरेलू कीमतें और तृतीय देशों की कीमतें संकुचित बैंड में हैं। कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को जापान मूल की संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं। इसके साथ ही जांच अवधि के बाद भी जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं।

60. एशिया में मांग-पूर्ति की स्थिति पर आईसीआईएस की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन से बाहर एशिया क्षेत्र में विकृत मार्जिन से प्रेरित उत्पादकों ने वर्ष 2015 में अपनी फिनोल/एसीटोन की आउटपुट को कम कर दिया है। एसीटोन की मांग में वृद्धि के वर्ष 2016 में आपूर्ति से पिछड़ने की संभावना है। निचले स्तर के क्षेत्रों में बिसफिनोल ए (बीपीए) और मिथिल मेथैक्राइलेट (एमएमए) की क्षमताओं में सीमित विस्तार हुआ है। वर्ष 2016 में बीपीए क्षमता में केवल उल्लेखनीय वृद्धि 1,10,000 टन/प्रति वर्ष की है, जो कि कोवेस्ट्रो द्वारा शंघाई स्थल पर बीपीए का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। उससे एसीटोन की खपत बढ़ कर 30,000 टन/प्रति वर्ष हो

जाएगी। आईसीआईएस, चीन द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2016 में चीन में 175,000 टन की संयुक्त एमएमए क्षमता युक्त तीन नए एमएमए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों में पूर्ण प्रचालन दरों पर 122,500 टन/वर्ष एसीटोन के प्रयुक्त किए जाने की आशा है। आईसीआईएस, चीन द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही में जिआंग्सू सेलबोट पेट्रोकेमिकल के नए 100,000 टन/प्रति वर्ष के एमएमए के शुरू हो जाने की आशा है, जबकि शांगडोंग होंगक्सू केमिकल 25,000 टन/वर्ष की अपनी एमएमए क्षमता का विस्तार कार्य पूरा कर लेगा। डोंगमिंग हुआई न्यू मेटेरियल का 50,000 टन/वर्ष की क्षमता के नए एमएमए संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इस संयंत्र के वर्ष 2016 में चालू हो जाने की संभावना है। आईसीआईएस की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गहन मंदी आने से भी विलयन के क्षेत्र में जो कि निचले स्तर का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें एसीटोन की मांग घटने की संभावना है और जिसका चीन में एसीटोन की खपत में 40-50% हिस्सा है। जैसा कि हाल ही में विनिर्माण और उत्पादक की कीमत के आंकड़ों से पता चलता है, चीन में आर्थिक स्थिति के और कमजोर होने के नए संकेत मिले हैं, जिससे एसीटोन की मांग में वृद्धि होने की सीमित संभावना का पता चलता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि चीन में मांग के कमजोर होने के कारण अक्टूबर, 2015 के बाद एसीटोन की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई।

61. एशिया के क्षेत्र में मांग, पूर्ति और कीमत की स्थिति का समग्र मूल्यांकन करने से ऐसा पता चलता है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो जापान और थाईलैंड से एसीटोन के कुछ निर्यात भारत को किए जा सकते हैं और आयात कीमत का अनुसरण कर सकते हैं, जैसा कि आईसीआईएस की रिपोर्ट में बताया गया है। इसलिए थाईलैंड से निरंतर पाटन होने की संभावना है और जापान से भी पाटन की पुनरावृत्ति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

झ. कार्यप्रणाली तथा क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

62. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति की जांच करने के संबंध में प्राधिकारी को निम्नोक्त की जांच करनी अपेक्षित होती है:-

- क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रहेगी और यदि हां, तो क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के निरंतर जारी रहने की संभावना है।
- ऐसे मामलों में जिनमें घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है, क्या पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

63. इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने की कार्रवाई करने से पहले इसकी जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण निरंतर आर्थिक क्षति होती रहेगी। घरेलू उद्योग आर्थिक क्षति की जांच, पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-2 के अनुसार है।

ब. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ब 1. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

64. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाताओं के निवेदनों में विरोधाभास है। एक ओर तो घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से कोई सुधार होने का पता नहीं चलता है और दूसरी ओर घरेलू उद्योग का यह दावा है कि निम्न स्तर पर निरंतर पाटन

- हो रहा है तथा घरेलू उद्योग को पाटन के निम्न स्तर के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। लेकिन यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- (2) बाजार सूचना के अनुसार यह ज्ञात है कि संबद्ध वस्तुओं के अधिकतर आयात अग्रिम लाईसेंस स्कीम के अंतर्गत जांच अवधि के साथ-साथ क्षति अवधि दौरान किए गए हैं। उक्त स्कीम के अंतर्गत अपने निर्मित उत्पादों को निर्यात करने का इच्छुक कोई भी घरेलू उत्पादक उक्त अग्रिम लाईसेंस स्कीम के अंतर्गत अपने कच्चे माल का आयात कर सकता है। ऐसी स्कीम का लाभ यह होगा कि इस अग्रिम लाईसेंस स्कीम के अंतर्गत किया गया कोई भी आयात, किसी भी पाटन-रोधी शुल्क अथवा सुरक्षा शुल्कों से मुक्त होगा। इस मामले में एक आवेदक, एसआई ग्रुप ने अग्रिम लाईसेंस स्कीम के अंतर्गत अत्यधिक मात्राओं में संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को एसआई ग्रुप के आयातों को शुल्क अदा किए गए और शुल्क मुक्त आयातों में पृथक् रूप से वर्गीकृत और उनका विश्लेषण करना चाहिए।
 - (3) *बेलकेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीएसटीएटी, चेन्नई, 2001 (289) ई.एल.टी. 444 (मद्रास) और डेट एलेक्ट्रिक फाईबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2010 (253) ई.एल.टी. (ट्राई-दिल्ली) के मामलों में दिए निर्णय का हवाला देते हुए प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों को अभिज्ञात किया जाना चाहिए तथा क्षति और पाटन की जांच करने के लिए उन्हें आयात की मात्राओं में से बाहर माना जाना चाहिए।*
 - (4) एचओसीएल को कोई भी क्षति उसकी अपनी अकुशलताओं, प्रचलनात्मक कमियों और अन्य बाधाओं (सेट-बैक्स) के कारण हुई हैं और वह दशकों से पाटन-रोधी विधि से संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि वर्ष 2002 से शुरू की गई अनेक जांच से पता चलता है।
 - (5) वर्ष 1999 में सुरक्षा जांच में एचओसीएल ने सुरक्षा शुल्क के बदले एक समायोजन योजना प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता का विस्तार करने और लागत को कम करने के लिए कुछ पृथक् योजनाओं को शामिल किया था, चूंकि उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उनके द्वारा अभिज्ञात किया गया एक कारण अर्थव्यवस्था के पैमाने थे। स्वीकृत किए गए ऐसे तथ्य और समायोजन योजनाओं के बावजूद भी एचओसीएल की क्षमता अभी भी उसी स्तर पर स्थिर बनी हुई है, जिस पर वह वर्ष 1999 में थी।
 - (6) वर्तमान याचिका में एचओसीएल ने यह स्वीकार किया है कि लंबे समय से उनके संयंत्र के बंद होने का कारण कच्चे माल की कमी होना और अन्य मुद्दे थे, जिनका संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन से कोई संबंध नहीं है। मूल मंत्रालय से अनेक प्रकार की सहायता और विभिन्न पाटन-रोधी शुल्कों से राहत प्राप्त होने के बावजूद बीआईएफआर द्वारा एसआईसीए के अंतर्गत एचओसीएल को एक रूग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था और वह लगभग एक दशक से रूग्ण बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर संसदीय समिति की नौवीं रिपोर्ट (2015-16) पर विश्वास किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अपने प्रस्ताव को महानिदेशक, सुरक्षा को प्रस्तुत करने के 16 वर्षों के बाद भी एचओसीएल ने आधुनिक जिओलाईट केटेलिस्ट प्रणाली का उपयोग कर के क्यूमेने का विनिर्माण करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत नहीं किया है।
 - (7) इससे यह पता चलता है कि आरोपित पाटन के कारण उनको कोई क्षति नहीं हुई है और याचिकादाता माननीय प्राधिकारी के समक्ष अयथार्थ विवरण प्रस्तुत करके पाटन-रोधी विधि का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इससे एचओसीएल को अपना विस्तार करने और बड़ी हुई मांग को पूरा करने में उसकी अकुशलता और पहल प्रयास करने की कमी को दूर करने की असमर्थता का पता चलता है।
 - (8) एचओसीएल ने हाल ही के वर्षों में जिनमें जांच की अवधि भी शामिल है, अपने संयंत्र के निरंतर बंद रहने के बारे में बार-बार और सुस्थिर निवेदन किया है। वर्ष 2005 से एचओसीएल को भारतीय विधि के अनुसार रूग्ण घोषित किया गया है। हाल ही में अपरिष्कृत कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आने के कारण एचओसीएल के फिनोल विनिर्माता संयंत्र को दुबारा बंद करना पड़ गया है। संयंत्र के इस प्रकार से

- निरंतर बंद होने से घरेलू बाजार में आपूर्ति करने में एचओसीएल की क्षमता प्रभावित हुई है और उसके परिणाम स्वरूप एचओसीएल के कार्य-निष्पादन को क्षति हुई है। वास्तव में एचओसीएल ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि कच्चे माल की कमी के कारण उसके संयंत्र को निरंतर बंद करना पड़ा है, जिसका संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन से कोई सह-संबंध नहीं है।
- (9) एचओसीएल ने स्वीकार किया है कि उसका रासायनिक संयंत्र अभी भी बंद पड़ा हुआ है और तब भी याचिकादाताओं का यह दावा है कि आरोपित पाटन के कारण उनके उत्पादन और बिक्रियों के स्तरों में गिरावट आ रही है।
 - (10) कार्यशील पूंजी की घोर कमी होने के फलस्वरूप भी उत्पादन बंद करना पड़ा है। कंपनी ने सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में ऐसा उल्लेख किया है कि कोची रिफायनरी जो कि कच्चे माल की आपूर्ति कर रही थी, ने कंपनी को निरंतर आपूर्ति करने से मना कर दिया है क्योंकि उसकी ओर 90 करोड़ रूपए का ऋण बकाया है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को दुबारा लागू करना, बमुश्किल से उनको संयंत्र के प्रचालन में सहायक होगा।
 - (11) देश में मांग और पूर्ति के बीच व्यापक अंतर व्याप्त है जिसके लिए आयात करना अपरिहार्य है।
 - (12) घरेलू उद्योग की क्षति का कारण आयात नहीं बल्कि विभिन्न अन्य कारक हैं जिनका विशेष रूप से उल्लेख संसदीय समिति की रिपोर्ट में किया गया है। इन कारकों में उत्पादन की उच्च लागत, मांग और पूर्ति में व्याप्त अत्यधिक अंतर, निकृष्ट प्रौद्योगिकी, संयंत्र की कमियां, संयंत्र का बंद होना, दूरदृष्टि की कमी और घटिया प्रबंधन शामिल हैं।
 - (13) संयंत्र के बार-बार और सुस्थिर रूप से बंद रहने के कारण उत्पादन को नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग ने बाजार के 22% हिस्से को गंवा दिया है, जबकि संबद्ध देशों के आयातों को बाजार के हिस्से में केवल 4% का लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें अधिकतर हिस्सा, कोरिया और सिंगापुर से आयातों का है।
 - (14) भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य अकेले उत्पादक एसआई ग्रुप का कार्य-निष्पादन काफी अच्छा है, जिससे एचओसीएल की आंतरिक कमियों का पता चलता है, जो कि उसके बाजार के हिस्से को गंवाने का कारण है।
 - (15) निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमता को उनके प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। किसी भी विधि अथवा विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक उत्पादक को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ऐसी अवधारणा है कि विश्व में कोई भी अतिरिक्त क्षमता, केवल भारत को नुकसान पहुंचाएगी और उपभोक्ताओं को आहत करेगी।
 - (16) कारणात्मक संबंध में कोई अतिक्रमण नहीं है क्योंकि संबद्ध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। कोरिया और अन्य देशों जिनमें संबद्ध देश शामिल नहीं है, से आयातों के भारी प्रभाव पड़े हैं। एचओसीएल ने यह माना है कि पाटन के लिए जिम्मेदार अन्य देशों से पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त करना है और न कि संबद्ध देश, चूंकि संबद्ध देशों पर लगाए गए शुल्कों को कभी भी हटाया नहीं गया है।

ब 2. घरेलू उद्योग के निवेदन

65. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है।

- ii. जांच अवधि में थाईलैंड से आयातों की मात्रा, आधार वर्ष में हुए आयातों से काफी अधिक थी तथा ये इतने अधिक थे जो कि संभावित स्थिति का निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ पाटन और क्षति की पुष्टि करते हैं।
- iii. जापान के संबंध में यह निवेदन है कि हालांकि वर्तमान अवधि में वहां से कोई आयात नहीं हुए हैं, लेकिन जापान ने तृतीय देशों को अत्यधिक मात्रा में निर्यात किए हैं, जिससे कीमत में कटौती होने और भारत को इन वस्तुओं के विपथन होने का पता चलता है। यदि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो आयातों की मात्रा में अधिक वृद्धि होने की संभावना है।
- iv. थाईलैंड के मामले में संबद्ध आयात भारत में समान उत्पाद की कीमत में कटौती कर रहे हैं। तथापि, जापान के मामले में तृतीय देशों को निर्यात ऐसी कीमतों पर किए जाते हैं जो कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने के बाद भी संबद्ध वस्तुओं का विपथन भारत की ओर करेंगी और घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती होने का नुकसान होगा।
- v. आयात घरेलू कीमत में कटौती कर रहे हैं और पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक कीमत ह्रास प्रभाव पड़ेगा।
- vi. जब कि इस समय पाटन-रोधी शुल्क का लागू होने के कारण थाईलैंड से कम मात्रा में आयात हो रहे हैं और जापान से कोई आयात नहीं हो रहा है, लेकिन यदि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो इन देशों से पाटन और अधिक गहन होंगे तथा आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- vii. देश में उत्पादों के निरंतर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति हो रही है।
- viii. अग्रिम लाईसेंस के मुद्दे पर विधि-शास्त्र ऐसा प्राधिकार देता है जिससे अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत आने वाली आयातों की मात्रा के कारण कीमत क्षति होती है। इसलिए इसे बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ix. एसआई ग्रुप के आयात शुल्क मुक्त आयात हैं, जो कि निर्यात दायित्व पर किए जाते हैं तथा इसलिए वे वर्तमान जांच के लिए चिंता का कारण नहीं हैं।
- x. निर्दिष्ट प्राधिकारी का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वे एसआई ग्रुप के आयातों को शुल्क दत्त और शुल्क मुक्त आयातों में पृथक् रूप से वर्गीकृत करें और उनकी जांच करें।
- xi. मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर होने से स्वभाविक रूप से आयात यथोचित होते हैं लेकिन देश में उत्पाद का पाटन नहीं। डीएसएम इंडेमिट्सु के मामले में सीईएसईटी के निर्णय के अनुसार यदि निर्यातक भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, तो वे सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात कर सकते हैं, लेकिन पाटित मूल्य पर नहीं और न ही बाजार को हथियाने के लिए।
- xii. विगत में प्राचलों के पूरा होने पर ही पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए हैं।
- xiii. प्रौद्योगिकी में विकास होने के कारण क्षति का दावा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग को वैसे ही देखना चाहिए जैसा वह है और न कि आदर्श दशाओं के परिप्रेक्ष्य में।

- xiv. जहाँ तक कि यदि एचओसीएल को एक रूग्ण उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो पाटन के सिवाए क्षति के लिए किन्हीं अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराए बिना एक ऐसा विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या वह अन्य कारणों से एक रूग्ण कंपनी थी।
- xv. लंबे समय से पाटन होने के परिणामस्वरूप कच्चे माल की कमी और परिणामी क्षति हुई है। इसमें सीधा कारणात्मक संबंध है।
- xvi. पाटन होने के कारण क्षति होती है जिसके परिणाम स्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आती है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटे होते हैं, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी कच्चा माल प्राप्त कर सकने में असमर्थ होती है। इस कारणवश उत्पादन का नुकसान होता है, जिसका क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके परिणामस्वरूप कम उत्पादन होने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ती है और उनसे होने वाले घाटे आगे नकदी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। आरोहित नकदी प्रवाह, कच्चा माल प्राप्त करने की कंपनी के समर्थता पर प्रभाव डालती है और यह चक्र लंबे समय तक निरंतर चलता रहता है क्योंकि बाजार पाटन से प्रभावित होता है।
- xvii. एसआई समूह के बारे में हितबद्ध पक्षकारों ने उसके कार्य-निष्पादन में अंतर होने पर ध्यान संकेन्द्रित किया है, जब कि विधि के अंतर्गत आवश्यकता कार्य-निष्पादन में गिरावट आने (अथवा गिरावट आने की संभावना) की जांच करने की है।
- xviii. अन्य पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि वर्तमान स्रोतों से “कोई क्षति नहीं हुई है अथवा क्षति होने की कोई संभावना नहीं है”।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति की समीक्षाओं/सिफारिशों का हवाला दिया है और उसकी रिपोर्ट की विषय सामग्री को यह दर्शाने के लिए विस्तार से ऐसे पढ़ा है, जैसे कि संसदीय समिति ने एचओसीएल के प्रतिकूल कार्य-निष्पादन के लिए पूर्णतया कोई भिन्न कारण पाए हैं तथा एचओसीएल ने अपनी कठिनाईयों में अपने उत्पाद में पाटन को गलत ढंग से जिम्मेदार ठहराया है।
- xx. विगत अनेक वर्षों तक पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग भिन्न स्रोतों से अनुचित प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण नुकसान उठा रहा है। इसका प्रमुख कारण विश्व बाजार में अत्यधिक वेशी होना तथा वैश्विक उत्पादकों का वस्तुओं का पाटन करने में सक्षम होना है। यदि घरेलू उद्योग को यथोचित पाटन-रोधी शुल्कों से सहायता नहीं दी जाती है, तो एचओसीएल द्वारा उत्पादन का स्थगन करने के परिणाम स्वरूप उसका संयंत्र पूरी तरह से बंद हो सकता है।
- xxi. यदि एचओसीएल में किसी प्रकार का कुप्रबंधन है, तो उसका निदान संसदीय समिति से कराके ठीक ही किया गया है क्योंकि एचओसीएल सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को विधि के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद केवल शुल्क लगाने की सिफारिश करनी होगी। समिति का ऐसा परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करता है।
- xxii. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के प्रमाणों के विपरीत समिति ने पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने के “नकारात्मक” प्रभाव को एचओसीएल की विषम स्थिति के जिम्मेदार कारकों में से एक प्रमुख कारक माना है।

- xxiii. पाटन ने केवल एचओसीएल को ही कुप्रभावित नहीं किया है, बल्कि पाटन से एसआई ग्रुप को भी उससे नुकसान हुआ है। निर्विष्ट प्राधिकारी कृपया इन दोनों कंपनियों के क्षति विवरणों की जांच कर सकते हैं।

ख 3. प्रकटन पश्चात प्रतिवादी द्वितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

66. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने दृष्टिकोण को अधिकतर दोहराया है और अन्य बातों के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. कीमत में कटौती सकारात्मक है और पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ने की संभावना है।
- ii. एचओसीएल ने उत्पाद का गहन पाटन होने के कारण अपने उत्पादन का स्थगन कर दिया था क्योंकि पाटन ने उसके वर्तमान प्रचालन को पूर्णतया गैर-अर्थक्षम बना दिया था। एचओसीएल इस व्यवसाय से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है। उसने अपना उत्पादन का स्थगन मात्र किया था, जो कि उसने फिर से शुरू कर दिया है और प्राधिकारी द्वारा इस आशय का मांगा गया प्रमाण पत्र भी उन्हें प्रदान कर दिया गया है।
- iii. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। एसआई समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से उसके लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में अत्यधिक गिरावट आने का स्पष्ट पता चलता है। जब कि एसआई समूह एक निजी उद्यम है और एचओसीएल सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। कंपनी को हो रहे वित्तीय घाटों ने कंपनी को अपना उत्पादन कम करने के लिए विवश कर दिया है।
- iv. जांच अवधि के दौरान बिक्री वसूली, उत्पादन की लागत से कम रही है।
- v. भारतीय बाजार में उत्पाद के वैश्विक बेशी के पाटन के कारण एचओसीएल अपने कार्य-निष्पादन में और सुधार नहीं कर सका है और उसे फिर से घाटे हो रहे गए हैं।
- vi. पाटन संबंध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग को अभी तक निरंतर क्षति हो रही है।
- vii. क्षमता के बेहतर उपयोग करने के बावजूद भी एचओसीएल को जांच अवधि के दौरान अत्यधिक प्रतिकूल कीमत से नुकसान होता है।
- viii. विनिमय की अस्थिरता, मुद्रास्फीति, उच्च व्याज दरें और अनश्चित स्टॉक बाजार जैसा कोई भी कारक घरेलू उद्योग की क्षति के दावे के लिए जिम्मेदार नहीं है। जहां तक घरेलू उद्योग और मौजूदा उत्पाद का संबंध है, इन कारकों में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ऐसी गिरावट अन्य कारकों के कारण नहीं है।
- ix. थाईलैंड से अत्यधिक आयात हुए हैं, जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो थाईलैंड के उत्पादकों के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति होने की संभावना है।
- x. एचओसीएल ने फिनोल और एसीटोन की लागत निर्धारित करने के लिए विभिन्न कार्य-प्रणाली नहीं अपनाई है। एचओसीएल ने सुसंगत तरीके से सूचना प्रदान की है।

- xi. संबद्ध प्राचलों से पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और इस प्रकार कारणात्मक संबंध होने की संपुष्टि होती है।
 - xii. मांग में संकुचन एक संभावित कारण नहीं है, जो कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।
 - xiii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन होने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
 - xiv. व्यापार को प्रतिबंधित करने की ऐसी कोई प्रथा नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।
 - xv. उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में अभी न तो कोई परिवर्तन हुआ है और न ही निकट भविष्य में उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए प्रोद्योगिकी में विकास होना क्षति का कारक नहीं है।
 - xvi. प्राधिकारी द्वारा सभी विगत मामलों में पाटन के तथ्य की पुष्टि की गई है। फिनोल और एसीटोन की अत्यधिक वैश्विक वेशी क्षमता से स्पष्ट पता चलता है कि वह भारत में उत्पाद के पाटन का कारण है। ऐसी अत्यधिक वेशी क्षमताओं के निरंतर बने रहने की संभावना है। वास्तव में एसीटोन की मांग में समानुपात वृद्धि के बिना फिनोल की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विश्व बाजार में एसीटोन की कीमतों पर और अधिक भार पड़ेगा।
67. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं:-
- यदि अग्रिम लाईसेंस आयातों में प्रचलित आयातों की मात्राएं (अथवा कीमतें) घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहीं हैं, तो कोई भी पाटन-रोधी शुल्क ऐसी क्षति को दूर नहीं कर सकेगा। जब तक नीति में व्यापक परिवर्तन नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक लगाए गए कोई भी पाटन-रोधी शुल्क याचिकादाताओं को अग्रिम लाईसेंस आयातों (चाहे वे पाटित हों अथवा नहीं) से संरक्षण प्रदान नहीं कर सकेगा।
 - जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का स्थगन करने के कारण आयात बढ़ गए हों। भारत में आयातों का अंतःप्रवाह पाटन को इंगित नहीं करता है, विशेषकर वर्तमान मामले में जिसमें जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का स्थगन कर दिया गया है। वास्तव में ऐसी प्रतिस्पर्द्धा स्वतंत्र बाजार का संकेतक मात्र है। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्राधिकारी द्वारा फिनोल के प्रकटन पश्चात विवरण के पैरा 7 में उल्लेख किया गया है, मुख्य लाभ अन्य गैर-संबद्ध देशों को हुआ है, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लग रहे हैं और न कि संबद्ध देश। इस पहलू से स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध देशों से कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
 - इस तथ्य के बावजूद कि जांच अवधि के अधिकतर समय में एचओसीएल द्वारा उत्पादन का स्थगन किए जाने के कारण लागत और कीमतें प्रभावित हुई हैं, फिर भी घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली क्षति रहित कीमत से ऊपर स्थिर बनी हुई है। इस विवरण से संबद्ध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विच्छेद होने का स्पष्ट पता चलता है क्योंकि आरोपित पाटित आयात से घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार से अपनी क्षति रहित कीमत वसूल करने में कोई कठिनाई होने का पता नहीं चलता है। केवल इस निष्कर्ष के कारण प्राधिकारी को अब अंतिम परिणाम जारी करना चाहिए और संबद्ध देशों से शुल्कों को समाप्त करने की सिफारिश करनी चाहिए।

- जांच अवधि के दौरान एसआई ग्रुप कंपनी पूरा उत्पादन कर रही थी और वह उसी अवधि में बाजार में अपने उत्पाद को अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर बेच रही थी, जिससे पता चलता है कि पाटित आयातों ने घरेलू कीमतों का ह्रास नहीं किया है अथवा कोई दबाव नहीं डाला है।
- एचओसीएल ने प्रोद्योगिकी के आधुनिकीकरण की कमी, कार्यशील पूंजी की कठिनाई और रिफाइनरी द्वारा पहले से उसकी ओर अधिक बकाया होने के कारण कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने जैसे आंतरिक कारकों के कारण अपना उत्पादन बंद कर दिया था और न कि संबद्ध देशों से आरोपित पाटन के कारण।

ब 4. प्राधिकारी द्वारा जांच

68. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को नोट कर लिया और और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू विधि को ध्यान में रख कर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणों की जांच कर ली है। तदनुसार प्राधिकारी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों के कारण होने वाली क्षति के निरंतर बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने की कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जांच करने की कार्रवाई करते हैं।

69. अनुबंध-2 के साथ पठित साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

70. वर्तमान क्षति विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और उसके घरेलू उद्योग के साथ-साथ कीमतों और लाभप्रदता पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है, ताकि पाटन और क्षति के बीच यदि कोई कारणात्मक संबंध विद्यमान है, तो उसका पता लगाया जा सके।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने के लिए आवेदन पत्र एचओसीएल और एसआई इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा इस समीक्षा में क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ इनको घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। तथापि, जैसा कि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है, जितना संभव हुआ है, इन दोनों उत्पादकों के कार्य-निष्पादन की जांच यह देखने के लिए की गई है कि इन दोनों घरेलू उत्पादकों के कार्यचालन की स्थिति ठीक है क्योंकि एचओसीएल ने जांच अवधि में अधिकतर समय तक उत्पादन नहीं किया है, जिससे उनके कार्य-निष्पादन के सूचक अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

72. शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हाने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने की कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग के वास्तविक प्राचलों पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव की जांच की गई है।

क. पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव

(1) आयातों की मात्रा और आयातों में हिस्सा

73. डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों की जांच की गई है, ताकि आयात की मात्राओं और कीमतों की प्रवृत्ति तथा घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके, जो कि निम्नानुसार हैं:-

आयात - (मात्रा)	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
संबद्ध देश	मी. टन	1,003	14,014	8,944	2,629	3,880
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,397	892	262	387
जापान	मी. टन	0	4,919	4,900	0	0
थाईलैंड	मी. टन	1,003	9,095	4,044	2,629	3,880
जिन देशों पर पाटन- रोधी शुल्क लग रहे हैं	मी. टन	75,163	83,466	86,662	1,17,074	1,75,611
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	115	156	234
अन्य देश	मी. टन	2,691	5,431	444	63	95
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	16	2	4
कुल	मी. टन	78,857	1,02,911	96,050	1,19,767	1,79,586
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	122	152	228

74. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि क्षति की जांच करने की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में कुल आयातों में वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 52% की वृद्धि हुई है। तथापि, जब कि जांच अवधि सहित क्षति की जांच करने की अवधि में अधिकतर समय तक जापान से कोई आयात नहीं हुआ है, इस अवधि के दौरान थाईलैंड से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो कि वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 162% हैं। लेकिन थाईलैंड से आयात, कुल आयातों का लगभग 2.2% मात्र हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि अनेक देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहे हैं, इस अवधि के दौरान इन देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और ये कुल आयातों का लगभग 97.75% बनते हैं, जब कि अन्य देशों से आयात नगण्य हैं।

75. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों की अत्यधिक मात्रा अग्रिम लाईसेंस स्कीम के अंतर्गत आती है, जो कि पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान किए बिना है और इसलिए ऐसे आयातों को क्षति विश्लेषण से पृथक् रखा जाना चाहिए। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों की मात्रा की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

(2) मांग का मूल्यांकन और बाजार के हिस्से

76. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू बाजार में मांग और पूर्ति के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त है। भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योगफल के रूप में निर्धारित मांग के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

भारत में मांग	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	48,442	39,897	37,539	26,566	39,849
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	77	55	82
एचओसीएल	मी. टन	27,419	18,143	16,222	4,839	7,258

एस आई ग्रुप	मी. टन	21,023	21,754	21,317	21,727	32,590
संबद्ध देशों से पाटित आयात	मी. टन	1,003	14,014	8,944	2,629	3,880
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,397	892	262	387
जापान	मी. टन	0	4,919	4,900	0	0
थाईलैंड	मी. टन	1,003	9,095	4,044	2,629	3,880
कुल आयात	मी. टन	78,857	1,02,911	96,050	1,19,767	1,79,586
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	122	152	228
मांग	मी. टन	1,27,299	1,42,808	1,33,589	1,46,333	2,19,435
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	105	115	172

77. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जबकि मांग स्थिर बनी हुई है, आयातों में वृद्धि हुई है तथा विशेष कर जांच अवधि में घरेलू बिक्रियों में अत्यधिक गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण एचओसीएल की बिक्रियों में गिरावट आना है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विभिन्न व्यवसायिकों के बाजार हिस्से में प्रवृत्ति निम्नानुसार थी:-

मांग में बाजार का हिस्सा	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	38%	28%	28%	18%	18%
एचओसीएल (घरेलू उद्योग)	%	22%	13%	12%	3%	3%
एस आई ग्रुप	%	17%	15%	16%	15%	15%
संबद्ध देशों से आयात	%	1%	10%	7%	2%	2%
जिन देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहे हैं	%	59%	58%	65%	80%	80%
अन्य देश	%	2%	4%	0%	0%	0%
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

78. उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों के हिस्से में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण एचओसीएल के उत्पादन का कम होना है क्योंकि अन्य उत्पादक अपनी पूरी क्षमता में उत्पादन कर रहा है और बाजार के अपने हिस्से को बनाए रख रहा है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में वृद्धि होने के बाद थाईलैंड से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। लेकिन मुख्य लाभ ऐसे अन्य देशों को हुआ है, जिन पर शुल्क नहीं लग रहे हैं और जिन्होंने देश में बाजार की लगभग 80% मांग को अधिप्राप्त कर लिया है।

ख. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

(1) आयात कीमतों की प्रवृत्ति

79. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान विभिन्न देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतें निम्नानुसार हैं:-

आयात - (कीमतें)	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
संबद्ध देश	रूपए/कि.ग्रा.	49	55	59	68	68
जापान	रूपए/कि.ग्रा.		55	58		
थाईलैंड	रूपए/कि.ग्रा.	49	54	60	68	68
जिन देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहे हैं	रूपए/कि.ग्रा.	13	28	37	53	53
अन्य देश	रूपए/कि.ग्रा.	43	56	70	81	81
कुल	रूपए/कि.ग्रा.	41	54	57	71	71

80. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों की सीआईएफ कीमतें ऐसे अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक हैं, जिन पर शुल्क लग रहे हैं। अन्य देशों से आयातों की मात्रा नगण्य है।

(2) पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभाव

81. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत में कटौती होने के प्रभाव की जांच करने के लिए आयातों के पहुंच मूल्यों की तुलना घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली से की गई है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

विवरण	माप का यूनिट	थाईलैंड
आयात की पहुंच कीमत	रूपए/मी. टन	72,716
निबल बिक्री वसूली	रूपए/मी. टन	***
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क रहित)	रूपए/मी. टन	***
	%	0-10%
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क सहित)	रूपए/मी. टन	***
	%	0-10%

82. आंकड़ों से पता चलता है कि थाईलैंड से पाटित आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

पाटित आयातों के कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव

83. पाटित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना भी घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से की गई है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री होने का प्रभाव पड़ रहा है।

विवरण	माप का यूनिट	जापान	थाईलैंड
क्षति रहित कीमत	रूपए/मी. टन	***	***
पहुंच कीमत	रूपए/मी. टन	कोई आयात नहीं	72,716
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क रहित)	रूपए/मी. टन		(***)
	%		(5-15)%
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क सहित)	रूपए/मी. टन		(***)
	%		(5-15)%

84. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री होने का कोई प्रभाव नहीं डाला है, क्योंकि दत्त पाटन-रोधी शुल्क युक्त संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक था।

(3) कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण

85. चूंकि जांच अवधि के दौरान कम उत्पादन और बहुत कम क्षमता उपयोग होने के कारण घरेलू उद्योग की लागत अत्यधिक प्रभावित हुई है, इसलिए यह देखने के लिए कि पाटित आयातों के विद्यमान रहने पर घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक ह्रास हो रहा है, प्रवृत्तियों का उचित विश्लेषण करना संभव नहीं है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत और आयातों के पहुंच मूल्यों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:-

विवरण	माप का यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
बिक्रियों की लागत	सूचीबद्ध	100	152	193	226	226
बिक्रियों की कीमत	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
बिक्रियों की कीमत	सूचीबद्ध	100	131	137	159	159
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क सहित)	रूपए/मी. टन	53,031	59,444	64,207	72,716	72,716
कीमत में कटौती (पाटन-रोधी शुल्क सहित)	सूचीबद्ध	100	112	121	137	137

86. यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2012—13 से एचओसीएल के उत्पादन में अत्यधिक कमी होने के कारण घरेलू उद्योग की लागत अत्यधिक प्रभावित हुई है। तथापि, बिक्री कीमत की प्रवृत्ति संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों से अधिक बनी हुई है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि किसी अत्यधिक सीमा तक कीमतों ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

87. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग (एचओसीएल) का उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ था, बिक्रियों, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में दोनों घरेलू उत्पादकों के कार्य-निष्पादन की पृथक रूप से जांच यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों से इन दोनों उत्पादकों के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा था, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
क्षमता	मी. टन	45,500	45,500	47,140	38,927	58,390
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	104	86	128
एचओसीएल	मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	मी. टन	***	***	***	***	***
उत्पादन	मी. टन	50,236	41,669	37,080	26,801	40,201

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	74	53	80
एचओसीएल	मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	मी. टन	***	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	110.41%	91.58%	78.66%	68.85%	68.85%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	71	62	62
एचओसीएल	%	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	%	***	***	***	***	***
घरेलू विक्रियां	मी. टन	48,442	39,897	37,539	26,566	39,849
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	77	55	82
एचओसीएल	मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	मी. टन	***	***	***	***	***
केप्टिव विक्रियां	मी. टन	2,825	1,163	622	327	490
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	41	22	12	17
एचओसीएल	मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	41	22	12	17

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि समग्र क्षति अवधि के दौरान एसआई ग्रुप उत्पादन करने के लिए अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहा था, लेकिन वर्ष 2011-12 से उसके उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एचओसीएल की उत्पादन सुविधा जांच अवधि में केवल 119 दिनों के लिए प्रचालन में थी जिसके फलस्वरूप उसके उत्पादन में कमी आ गई और जांचअवधि के दौरान उसका क्षमता उपयोग कम हो गया।

89. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनेक आंतरिक कारकों के कारण एचओसीएल का कार्य-निष्पादन काफी लंबे समय से प्रभावित रहा है। दूसरी ओर याचिकादाताओं ने यह तर्क दिया है कि अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण कार्य-निष्पादन प्रभावित हुआ है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र जांच अवधि के दौरान कुछ देशों के कुछ उत्पादकों को छोड़ कर, संबद्ध देशों सहित प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों पर शुल्क लागू थे। इसके अतिरिक्त अन्य घरेलू उत्पादक की लगभग कुल उत्पादन क्षमता का उपयोग होने से घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन नहीं हो जाता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव होने से उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हो सकता है, जैसा कि एसआई ग्रुप के मामले में भी देखा गया है।

(2) लाभ/हानि, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

90. संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षति की जांच अवधि के दौरान एचओसीएल का वित्तीय निष्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
विक्रियों की लागत	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	193	226	226
एचओसीएल	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	137	159	159
एचओसीएल	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	रूपए/मी. टन	***	***	***	***	***
लाभ/हानि	रूपए/मी. टन	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	-32	-48	-48
एचओसीएल	रूपए/मी. टन	***	***	(***)	(***)	(***)
एसआई ग्रुप	रूपए/मी. टन	***	***	(***)	(***)	(***)
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	53	-24	-25	-37
एचओसीएल	लाख रूपए	***	***	(***)	(***)	(***)
एसआई ग्रुप	लाख रूपए	***	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति		100	73	-13	0	1

91. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एचओसीएल का संयंत्र जांच अवधि के 18 महीनों में केवल 119 दिनों के लिए प्रचालन में था। इसलिए संयंत्र के लंबे समय तक बंद रहने के कारण लागत अत्यधिक प्रभावित हुई है और इससे उत्पादन की सही लागत का पता नहीं चलेगा। विगत वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि एचओसीएल अपने घरेलू प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में उच्चतर लाभ मार्जिन के साथ संबद्ध वस्तुओं का उस समय तक एक कुशल उत्पादक था जब तक वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहा था। वर्ष 2011-12 से एचओसीएल के क्षमता उपयोग में गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप उसका मार्जिन घट गया और वर्ष 2012-13 से उसको परिणामी घाटे होने लगे। उसी समय अन्य घरेलू उत्पादक ने समग्र अवधि में निरंतर सार्थक लाभ मार्जिन अर्जित किया है, जिसमें वर्ष 2012-13 शामिल नहीं हैं क्योंकि उस दौरान प्रत्यक्षतः कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण उसे लाभ नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि एचओसीएल को नुकसान होने का कारण विचाराधीन अवधि के दौरान उसकी उत्पाद और बिक्री करने की अपनी निजी अक्षमता थी। इसलिए विचाराधीन अवधि के दौरान एचओसीएल के कम उत्पादन होने के कारणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

92. चूंकि एचओसीएल नामक एक घरेलू उत्पादक का संयंत्र विविध कारणों से काफी लंबे समय से प्रचालन में नहीं था, इसलिए अन्य अनिवार्य प्राचल इस स्थिति से संबद्ध नहीं हैं।

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध के समग्र मूल्यांकन

93. उपरोक्त क्षति प्राचलों की जांच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के एचओसीएल नामक एक घरेलू उत्पादक को उत्पादन के अत्यधिक कम होने के फलस्वरूप विप्लवपूर्ण घाटे हुए हैं। विप्लवपूर्ण भाग में यह स्थापित हुआ

है कि जापान से कोई आयात नहीं हुआ है। थाईलैंड से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं। दूसरे घरेलू उत्पादक ने निरंतर अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग किया है और सार्थक लाभ अर्जित किया है। इन परिस्थितियों में यह जांच करना अत्यावश्यक है कि एचओसीएल के उत्पादन में कमी और उसके परिणाम स्वरूप उसको हुए वित्तीय घाटे, संबद्ध देशों से पाटित आयातों अथवा अन्य कारकों के कारण हुए हैं।

94. एचओसीएल का उत्पादन नहीं होने और वित्तीय घाटे के रूप में उसको परिणामी क्षति होने के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने संसदीय समिति की रिपोर्टों का हवाला देते हुए और अन्य सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराते हुए यह तर्क दिया है कि एचओसीएल का उत्पादन यूनिट पाटन की बजाए आंतरिक अकुशलताओं और प्रबंधन समस्याओं के कारण बंद हो गया है। यह निवेदन किया गया है कि आधुनिक बनाए जाने में यूनिट की अक्षमता, आर्थिक पैमाने के आकार और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र को बंद करना पड़ा है और न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण।

95. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि एचओसीएल ने जांच अवधि के दौरान अपना उत्पादन स्थगन कर दिया था क्योंकि पाटित आयातों के कारण उत्पादन और बिक्रियां अर्थक्षम नहीं थीं और संयंत्र को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि एचओसीएल ने कोचीन रिफाइनरी से कच्चे माल की आपूर्ति की कुछ व्यवस्था होने से हाल ही में अपना उत्पादन फिर शुरू कर दिया है।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल ने फिनोल की लगभग 40,000 मी.टन और एसीटोन की 45,000 मी.टन की क्षमता से तथा कोचीन रिफाइनरी से कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करके अन्य अनुषंगी उत्पादों के लिए 1980 के दशक के अंत में अपना उत्पादन यूनिट स्थापित किया था। इसकी क्षमता और प्रोद्योगिकी शायद मांग की स्थिति और उस समय उपलब्ध प्रोद्योगिकी पर आधारित थी। उसके बाद मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई और साथ ही प्रोद्योगिकी भी उन्नत हो गई थी जैसा कि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्टों में उल्लेख किया है और कंपनी ने प्राधिकारियों के समक्ष निवेदन किए हैं। लेकिन कंपनी ने विभिन्न कारणों से उक्त संयंत्र की क्षमता को नहीं बढ़ाया है अथवा आधुनिक नहीं बनाया है। संयंत्र को उन्नत और आधुनिक बनाने की असमर्थता के साथ-साथ अनेक देशों से पाटन होने से कंपनी का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ है तथा शुरू में वर्ष 2002 में अनेक देशों से फिनोल और एसीटोन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे। तथापि, एचओसीएल को निरंतर घाटे होने के कारण वर्ष 2005 में उसके यूनिट को रूग्ण घोषित कर दिया गया था और वह अभी भी वीआईएफआर के अंतर्गत रूग्ण बना हुआ है।

97. कंपनी का राशयानी यूनिट जो कि पहले अनेक अन्य उत्पादों में लगा हुआ था और जिसमें अत्यधिक कार्यबल था, वर्ष 2013 से बंद पड़ा हुआ है। तथापि, कोचीन यूनिट जो कि कुछ अन्य उत्पादों के साथ फिनोल और एसीटोन का उत्पादन करता था, कुछ समय तक अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करता रहा है, लेकिन वह पूंजीगत समस्याओं से प्रभावित हो गया क्योंकि इस यूनिट का लाभ पहले से बंद किए गए अन्य यूनिटों के निर्धारित व्ययों की पूर्ति कर रहा था। कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कोचीन रिफाइनरी को अदा करने के लिए 90 करोड़ रूपए की अत्यधिक बकाया राशि होने के कारण रिफाइनरी द्वारा यूनिट को कच्चे माल की आपूर्ति बंद करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 के मध्य से कोचीन संयंत्र के उत्पादन का स्थगन कर दिया गया है।

98. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि कुछ स्रोतों को छोड़ कर जिन्हें संबंधित जांच में पाया गया था कि वे पाटन नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी प्रमुख स्रोतों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहे थे। इसलिए इस उत्पादक को क्षति होने के लिए उन आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

99. हितबद्ध पक्षकारों ने एचओसीएल में आधुनिकीकरण की कमी और कुशल उत्पादन विधियों को अपनाने तथा आर्थिक आकार पर क्षमताओं को बढ़ाने के मुद्दे भी उठाए हैं, जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों में उल्लेख किया है और क्षति के एक कारण के रूप में अन्य प्राधिकारियों के समक्ष उसने अपनी कटिबद्धता व्यक्त की है। प्राधिकारी नोट

करते हैं कि कंपनी में उत्पादन की सुविधाएं पुरानी हैं और अनेक स्रोतों से पाटन सहित विभिन्न कारकों के कारण उसने मुख्य आधुनिकीकरण नहीं किया है।

100. इसलिए एचओसीएल के कार्यों की स्थिति के समग्र मूल्यांकन से पता चलता है कि संयंत्र का बंद किया जाना, संबद्ध देशों से पाटित आयातों से नहीं बल्कि उसकी कार्यशील पूंजी और प्रबंधन के मुद्दों से संबंधित है क्योंकि उसे समग्र क्षति अवधि के दौरान इन आयातों के विरुद्ध पाटन-रोधी शुल्कों का संरक्षण प्राप्त था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन के लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वस्तुतः तथ्य यह है कि एचओसीएल ने कोचीन रिफाइनरी के साथ कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कुछ करारों के साथ उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया था, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्पादन का स्थगन, कच्चे माल और कार्यशील पूंजी से संबंधित मुद्दों के कारण था और न कि मुख्यतया संबद्ध देशों से पाटित आयातों कारण।

101. एसआई ग्रुप नामक अन्य घरेलू उत्पादक के कार्य-निष्पादन से किसी विशेष गिरावट का पता नहीं चलता है। उनका उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रियां स्थिर बनी हुई हैं तथा लाभप्रदता वर्ष 2011-12 के स्तर के सन्निकट है। इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस अवधि के दौरान इस कंपनी का कार्य-निष्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ हो, हालांकि सदृश कीमत बैंड में अनेक देशों से पर्याप्त निर्यात हा रहे हैं।

102. इसलिए प्राधिकारी पाटित आयातों और समस्त घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई विशेष कारणात्मक संबंध होना नहीं पाते हैं।

ठ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

103. चूंकि ऐसा नहीं पाया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, इसलिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जाना अप्रासंगिक है। तथापि, नियमावली के संबद्ध प्रावधानों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत के अनुसार तथा जांच अवधि के दौरान उत्पादन की क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य को ध्यान में रखते हुए आयातों का क्षति मार्जिन का आकलन निम्नानुसार है:-

विवरण	माप का यूनिट	जापान	थाईलैंड
क्षति रहित कीमत	रूपए/मी.टन	****	****
पहुंच कीमत	रूपए/मी.टन	कोई आयात नहीं	72,716
क्षति मार्जिन	रूपए/मी.टन		(****)
	%		(5-15)%

104. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक होने से जांच अवधि के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन का पता चलता है।

105. घरेलू उद्योग ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण, अनुबंध-2 और पाटन-रोधी नियमावली में दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार किया गया है और इसलिए क्षति रहित कीमत में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

ड. क्षति के निरंतर जारी रहने की संभावना

106. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से तृतीय देश को निर्यात के आधार पर वर्तमान कीमत कटौती और/अथवा संभावित कीमत कटौती से यह पता चलेगा कि यदि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो संबद्ध वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी। दूसरी ओर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को आंतरिक समस्याओं के कारण नुकसान हो रहा है। यह तर्क भी दिया गया है कि संबद्ध देशों में प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की उनकी केप्टिव खपत और अन्य कटिबद्ध क्रेताओं के लिए पूर्व वचनबद्धता के कारण संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

107. प्रकटन पश्चात अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने अपने मत को पुनः दोहराया है और यह तर्क दिया है कि मौजूदा शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों के निर्यातक अपनी आउटपुट को भारतीय बाजार में अधिक सरणीबद्ध करेंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही अतिरिक्त क्षमताएं विद्यमान हैं और वे अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं। वास्तव में जैसा कि प्रकटन पश्चात विवरण में स्वीकार किया गया है, थाईलैंड में उत्पादक अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। वे ऐसी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग, अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए करेंगे और उनकी पहली पसंद भारत होगी क्योंकि यहां उत्पाद की व्यापक मांग है। जांच अवधि के बाद पाटित कीमतों पर निरंतर आयात हो रहें हैं और उनमें वृद्धि हुई है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहने से ऐसा स्पष्ट आभास होता है कि क्षति की संभावना है।

108. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के बाद के आंकड़ों से थाईलैंड से आयातों की मात्रा के अत्यधिक बढ़ने का पता नहीं चलता है, जब कि जापान से आयात निरंतर शून्य बने हुए हैं, हालांकि घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद हो जाने के कारण मांग और पूर्ति में व्यापक अंतर व्याप्त है। सभी स्रोतों से आयातों के कीमत स्तर से कीमतों में गिरावट आने का पता चलता है जिसका कारण कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आना है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि थाईलैंड की तृतीय देशों में क्रेताओं के प्रमुख बाजारों में पूर्व वचनबद्धता होने के साथ-साथ उसकी अपनी निजी केप्टिव खपत के कारण पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

109. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जांच अवधि के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुआ है। क्षति की जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से निरंतर पाटन हुआ है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि संबद्ध देशों में प्रमुख उत्पादकों की क्षमताओं और मांग-पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से निकट भविष्य में गहन पाटन होने की संभावना नहीं है। जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों से थाईलैंड से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने का पता नहीं चलता है, जब कि जापान से आयात निरंतर शून्य बने हुए हैं, हालांकि घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद हो जाने के कारण मांग और पूर्ति में व्यापक अंतर व्याप्त है। सभी स्रोतों से आयातों के कीमत स्तर से कीमतों में गिरावट आने का पता चलता है जिसका कारण कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आना है। आईसीएस की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है कि अक्टूबर, 2015 के बाद से एशियाई क्षेत्र में सभी देशों में एसीटोन की कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है। इसलिए संबद्ध देशों से आयात की कीमतें, असाधारण कीमत चलन को नहीं दर्शाती हैं, जिससे ऐसा पता चले कि जांच अवधि के बाद गहन पाटन हुआ है।

110. घरेलू उत्पादकों के जांच अवधि के बाद (अक्टूबर-मार्च, 2015) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में कोई उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन अन्य उत्पादक ने निरंतर अपनी लगभग पूरी क्षमता का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त विगत भाग में किए गए विश्लेषण से सिद्ध होता है कि एचओसीएल के उत्पादन का स्थगन, मुख्यतया उसकी आंतरिक समस्याओं के कारण रहा है, जो कि कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता तथा कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता को देय बकाया राशि के कारण उत्पन्न हुई थी। इसलिए यह

प्रश्न उठता है कि यदि शुल्कों को निरंतर जारी रखा जाता है, तो क्या कंपनी अपने उत्पादन को बहाल करने में सक्षम होगी।

111. विभिन्न कारकों की जांच और प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कार्यशील पूंजी और प्रबंधन के मुद्दों का निवारण किए बिना यूनिट उत्पादन और बिक्री को बहाल करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसे संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटन-रोधी शुल्कों का संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। हाल ही में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के साथ कुछ समझौता करके उत्पादन को शुरू करने की प्रक्रिया अभी स्थापित की जानी है। इसके अतिरिक्त शुल्क लागू करने के बाद अन्य स्रोतों से आयात निम्न कीमतों पर होते हैं। इसलिए मामले के वास्तविक सांचे में प्राधिकारी का यह विचार है कि हालांकि उद्योग को निरंतर क्षति होती रहेगी जो कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण नहीं होगी और उपायों को निरंतर जारी रखना यूनिट को बहाल करने में तब तक सहायक नहीं होगा, जब तक कि अन्य उपाय नहीं कर लिए जाते हैं।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

112. सामान्यतः पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में समान अवसरों वाली स्थिति सृजित करके खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके। तथापि, इस मामले में एक घरेलू उत्पादक ने उन देशों से जिनके विरुद्ध यह समीक्षा शुरू की गई थी, पाटित आयातों से भिन्न कारकों के कारण अपना उत्पादन बंद कर दिया था। अन्य घरेलू उत्पादक समीक्षा की अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावित नहीं हुआ है। घरेलू बाजार में मांग और पूर्ति के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त है जिसके कारण आयात करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों को आगे पांच वर्ष की अवधि तक नहीं बढ़ाया जाता है, तो उससे न तो संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हितों और न ही प्रयोक्ता उद्योग के हितों की बेहतर ढंग से पूर्ति होगी।

ण. निष्कर्ष और सिफारिशें

113. प्राधिकारी ने विधि के अनुसार इस समीक्षा की जांच शुरू की थी और उसका संचालन किया था तथा वर्तमान पाटन, क्षति तथा घरेलू उद्योग की क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संबंध तथा शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति की जांच की थी। पूर्ववर्ती पैराओं में यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि समीक्षा की अवधि के दौरान जापान से संबद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं हुआ है। थाईलैंड से निरंतर पाटन हो रहा है लेकिन यह बहुत कम स्तर पर है। यह भी पाया गया है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो भी थाईलैंड से वर्तमान स्तर पर निरंतर आयात हो सकते हैं और साथ ही जापान से भी कुछ आयात हो सकते हैं, लेकिन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के गहन पाटन की पुनरावृत्ति होने की सन्निकट कोई संभावना नहीं है। यह भी स्थापित हो गया है कि हालांकि समीक्षा अवधि के दौरान एक घरेलू उत्पादक को नुकसान हुआ है, लेकिन उसको ऐसी क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों के कारण हुई है। समीक्षा अवधि के दौरान अन्य घरेलू उत्पादक का कार्य-निष्पादन अत्यधिक प्रभावित नहीं हुआ है और यदि उसमें कोई गिरावट आई है, तो उसके लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है क्योंकि इन्हीं कीमत स्तरों पर अन्य देशों से भी आयात हो रहे हैं।

114. जांच से यह भी ऐसा पता चलता है कि यदि एचओसीएल के लिए शुल्कों को बढ़ा दिया जाता है, तब भी वह अपने उत्पादन को उस स्तर पर तब तक बहाल करने में सक्षम नहीं होगी जो कि अर्थक्षम हो और जब तक कि कंपनी को प्रभावित करने वाले अन्य मूलभूत मुद्दों का निदान नहीं कर दिया जाता है। चूंकि दो घरेलू उत्पादकों में से एक उत्पादक कंपनी उत्पादन नहीं कर रही है, जिसके कारण देश में मांग और पूर्ति के बीच व्यापक अंतर व्याप्त हो गया है। इसलिए यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों को आगे पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ा

दिया जाता है, तो उससे न तो संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हितों की और न ही प्रयोक्ता उद्योग के हितों की बेहतर ढंग से पूर्ति हो सकेगी।

115. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्कों को निरंतर लागू रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्राधिकारी, जापान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर सीमा-शुल्क की दिनांक 18 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2011-सीमा-शुल्क द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखे जाने की सिफारिश नहीं करते हैं।

116. निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के खिलाफ कोई भी अपील, संबद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला , अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

Final Finding

Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Acetone originating in or exported from Japan and Thailand.

No.15/29/2014: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

1. Having regard to the above Rules, the Designated Authority had initiated the original investigation concerning imports of Acetone, originating in or exported from Japan and Thailand, vide Notification No. 14/31/2009-DGAD dated 3rd September, 2009. The Designated Authority notified the Preliminary Findings recommending provisional anti-dumping duties on 16th February, 2010. Provisional duties were imposed vide Customs notification no. 45/2010- Customs dated 9th April 2010. The Final Findings Notification was issued by the Authority on 19th January, 2011 recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from Japan and Thailand. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 36/2011-Customs, dated 18th April, 2011, for a period of 5 years from 9th April 2010, i.e., upto 8th April 2015.
2. M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (hereinafter also referred to as HOCL), M/s SI Group India Ltd (hereinafter also referred as SI Group), filed a combined application before the Designated Authority for initiating a combined sunset review of the antidumping duties on import of Phenol and Acetone from Thailand and Japan, imposed vide Notification No.120 /2010-Customs dated 1st December 2010 and No. 36/2011-Customs dated 18th April, 2011. The petitioners alleged likelihood of continuation of dumping of the above goods, originating in or exported from Japan and Thailand (herein after referred to as the

subject countries) and consequent injury to the domestic industry and requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

3. In accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/29/2015-DGAD dated 7th April, 2015 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of Acetone (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The duty was extended by the Department of Revenue till 8th April 2016, vide notification no.16/2015-Customs (ADD), dated 22nd April 2015. The time period for completion of the investigation and notification of final finding of the Authority was extended by the Central Government till 6th July 2016, in terms of Rule 17 of the Rules.
4. Apart from the subject countries, antidumping duties are also in force on the subject goods originating in or exported from the European Union, Singapore, Korea RP, Chinese Taipei, USA, South Africa and Saudi Arabia. The scope of the present review is with respect to the duties in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from Japan and Thailand and covers all aspects of the previous investigation.

B. Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2).
 - ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iii. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make its views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).
 - i. PTT Phenol Co., Ltd. (PPCL)
 - ii. Chiba Phenol Co. Ltd. Shiodome
 - iii. Mitsubishi Chemicals
 - iv. Mitsui & Co., Ltd. ("MBK"), Japan
 - v. M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Limited, Singapore
 - vi. Mitsubishi Chemical Corporation ("MCC")
 - vii. Sunitomo Corporation
 - viii. Mitsui Chemicals, Inc
 - iv. The following producers/exporters of the subject goods in the subject countries have filed their questionnaire responses
 1. M/s PTT Phenol Company Limited, Thailand (Producer)
 2. M/s MITSUI & CO., LTD., JAPAN, (Exporter)
 3. M/s MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD., Singapore (Exporter)

- v. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):
1. M/s. C.J. Shah and Company
 2. M/s. Hareesh Kumar & Co., Mumbai
 3. M/s. PCL Oil & Industries
 4. M/s. Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.
 5. M/s. Sonkamal Enterprises, Mumbai
 6. M/s. Khetan Brothers
 7. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
 8. M/s. Acron Enterprises
 9. M/s. Naiknavare Chemicals Limited
 10. M/s. Paras Dyes & Chemicals
 11. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited, Gujarat
 12. M/s. United Phosphorus Ltd., Mumbai
 13. M/s. Resins & Plastic Ltd.
 14. M/s. Kailash Polymers
 15. M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.
 16. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
 17. M/s. Meghdev Enterprises
 18. M/s. Satguru International
 19. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.
 20. M/s. Karmen International (P) Ltd.
 21. M/s. High Polymer Labs Ltd.
 22. M/s. Rainbow colours & Chemicals
 23. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 24. M/s. NGP Industries Ltd.
 25. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujrat Ltd.
 26. M/s. India Glycols Ltd.
 27. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
 28. M/s. National Plywood Industries Ltd.
 29. M/s. Kundan Rice Mills Ltd.
- vi. None of the importers of the subject goods has filed any questionnaire response or made any substantive submissions in this matter.
- vii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation was April 2013 –September, 2014 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
- viii. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was, procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), has been relied upon for the analysis in this investigation.
- ix. Exporters, producers, importers and other parties concerned with the subject goods, who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have not been treated as interested parties in this investigation.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties, in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent

- possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearings held on 20th January 2016. All the interested parties attending the hearings were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.
 - xiii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.
 - xiv. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry and the cooperating producers and exporters to the extent considered relevant and necessary. Additional/supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
 - xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xvi. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 17.06.2016 for the comments of the interested parties. The comments of the interested parties, to the extent they are relevant, have been addressed in this finding in appropriate places.
 - xvii. *** in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - xviii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.60.76 = 1US\$.

C. Scope of Product under consideration and like article

6. The product under consideration in the Final Findings of the original investigation of Phenol dated 8th October, 2010 was described as follows:

“The product under consideration is ‘Acetone’. The Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under sub-heading 29141100. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid. It is used in numerous organic syntheses either as a solvent or as an intermediate. Acetone is specifically used in manufacture of Isophoron, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate and also a solvent in the manufacture of paints/coatings. It is marketed in two forms-loose bulk and packed”.

7. Petitioners have submitted that Acetone produced by them are like article to the Acetone imported from

the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

8. The product under consideration is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under sub-heading 29141100.
9. No relevant submission has been made by the producers/exporters/ importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article. This being the sunset review investigation, the Authority holds that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original investigation.

D. Domestic Industry and Standing

10. As noted earlier the petition for the sunset review of the antidumping duty on Phenol and Acetone was filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) and M/s SI Group India Ltd. (SI Group). The Petitioners are the only producers of Phenol and Acetone in India and therefore, account for total Indian production. At the stage of initiation, it was submitted by the petitioners that M/s SI Group had imported these goods from several countries, including subject countries, both under duty free and duty paid schemes for captive consumption only and the imported goods were not sold in the domestic market. Pending further inquiry, the Authority, considered, at the stage of initiation, SI Group as an eligible domestic producer to be a constituent of domestic industry.

D.1 Views of the opposing interested parties

11. The opposing interested parties, in their submissions, have strongly argued for exclusion of SI Group from the scope of domestic industry for the purpose of the injury investigation and have *inter alia* submitted:
 - i. That SI Group has been excluded from domestic industry in the past on account of imports, which have been made in the present investigation also in the POI. It has been submitted that out of several investigations carried out by the Designated Authority, in most of the original investigations SI Group had been excluded from the scope of the domestic industry on account of imports. Therefore, SI Group's participation in this anti-dumping investigations has been highly inconsistent.
 - ii. That imports of SI Group account for large share of production and sales made by domestic industry. SI Group has imported from sources of alleged dumping and has benefitted by trying to shield itself by partaking in dumping activities.
 - iii. That whether the imports are for captive consumption or commercial sales is irrelevant since any imports directly or indirectly impact the commercial market in India. Even if SI Group used most of imports for captive consumption, it freed up production and inventory of the product under consideration for commercial sales, while also at the same time ensuring that the captive consumption was substituted by cheap dumped imports.
 - iv. that while it is undisputed that the Hon'ble Designated Authority has complete discretion to include a domestic producer which is also an importer, this discretion must be moored on the touchstone of reasonableness and equity. Therefore, the inclusion of SI Group as domestic industry must be based on a rational and objective examination of facts.

- v. That in plethora of cases decided by the Authority in the past (Anti-dumping investigation concerning imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia- 2010; Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA- 2012; Mid-term Review (MTR) Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications', originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand -2013, Electrical Insulators-2015, etc.) the issue has been decided by the Authority based on certain principles. In the light of the earlier precedents involving similar situations faced by the Authority, the key parameters typically examined by the Authority for exercising its discretion while excluding or including a domestic producer from the ambit of "domestic industry" are as follows:
- a. Quantum of Imports in Comparison to Production and Sales;
 - b. The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production, as opposed to importing activities;
 - c. If inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
- vi. That by juxtaposing the above information on SI Group with the identified parameters for the Authority to exercise its discretion, the following relevant factors would emerge:
- d. The imports made by SI Group account for a large share of not just production but also sales made by the domestic industry.
 - e. As is evident from the data that its imports from countries subject to anti-dumping duties/ongoing investigations are over 37% of the total production of SI Group.
 - f. Therefore, it is undisputed that SI Group has not just imported from sources of alleged dumping, but also benefitted from the alleged dumping and in the process shielded itself by partaking in the dumping activities.
 - g. The current activities of SI Group are merely a continuation of a long standing trend as also recognized in the previous investigations carried out by the Authority, whereby it is clear that SI Group has had a long commitment towards importing the product under consideration from sources of alleged dumping.
- vii. That the Authority may segregate and analyse the imports made by SI Group into duty paid and duty free imports and the impact thereto on its operations and margins, and make the same available for the interested parties so as to allow them to make meaningful submissions in this behalf.
- viii. That in light of the above, the Authority should exercise the wide discretion accorded to it under the Anti-dumping Rules in a judicious manner in consideration of the facts and evidence before it and exclude SI Group from the scope of the domestic industry for the purpose of the injury examination.

D.2 Views of the Petitioners

12. The petitioners, in their submissions, have argued that the petitioners in the present investigation namely, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and SI Group India Ltd, are the only producers of the product under consideration in the country. Although M/s SI Group India Ltd has imported subject goods these imports are not from the subject countries. Moreover, these imports have been made under duty exemption scheme for export production of downstream products. The company hasn't imported for

trading purposes and therefore this behaviour should not be considered as causing injury to domestic industry. It has been further argued that since imports by SI Group pertain to non-subject countries, they are not relevant for present investigation.

13. It has been further argued that the Designated Authority, in various Acetone and Phenol cases, has held that whether imports are for captive consumption or commercial sales is an important distinction. However, notwithstanding the above should the Authority consider that SI Group cannot be a part of domestic industry the Authority can exclude SI Group from the scope of domestic industry and proceed on the data/information pertaining to M/s HOCL alone.

D.3 Examination by the Authority

14. The Authority has examined the issue of eligibility of M/s SI Group to be treated as a part of the domestic industry for injury examination in the light of the above arguments put forth by the interested parties, the extant Rules and the jurisprudence evolved on the issue.
15. The Authority notes that SI Group and HOCL filed a combined application for initiation of a combined sunset review investigation covering both the products as the domestic industry, countries involved and period of investigation were same for both the products. At the time of investigation SI Group claimed that they had imported certain quantities of Phenol during the proposed POI from various countries under duty exemption schemes for export production and certain quantities were imported, from various countries, including the countries under investigation, with payment of applicable duties for captive production of downstream products. The Company further declared that they imported certain quantities of Acetone under duty exemption schemes for export processing. It was declared that they have not sold any imported goods in the domestic market. Based on these declarations SI Group was included in the scope of the domestic industry at the time of initiation pending further inquiry into the issue.
16. During course of the investigation it has been found that during the POI SI Group imported 12246.43 MTs of Phenol out of which 7455.732 MTs were imported under duty exemption schemes for export production and remaining 4745.346 MTs were imported duty paid. Out of the duty paid imports 45.35 MTs were sold in the domestic market. It is further noted that all the imports are from countries attracting antidumping duty and 800 MTs have been imported from Thailand, which is one of the countries under investigation in this case. The imports of this Company are about 23% of its own production of Phenol during the POI. Similarly, SI Group imported 9924 MTs of Acetone under duty exemption schemes for export production. It is further noted that all the imports of Acetone are from countries attracting antidumping duty though no imports have been made from the countries under investigation. The imports of Acetone are about 30% of its own production during the POI.
17. The Authority further notes that in its submissions as recorded above the Company had argued that since imports by SI Group pertain to non-subject countries they are not relevant for present investigation. It has been further argued by the petitioners that SI Group did not import the goods for trading purposes and therefore, this behaviour should not be considered as causing injury to domestic industry though about 45MTs of duty paid Phenol imported by this Company was sold in the market during the POI. Investigation also reveals that SI Group continues to import substantial volumes of both Phenol and Acetone during the post POI period of these two investigations. The past history of the Company also shows that they have been consistently importing the goods for their own consumption.
18. With this factual position of the case the Authority turns to the definition of the domestic industry and the discretion available to it under the extant Rules. Rule 2(b) of the Antidumping Rules provides as under:

2. (b) *"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

19. In the instant case one of the complaining domestic producers, i.e., SI Group, has been importing of both Acetone and Phenol for its captive consumption largely for export production. This fact was also before the Authority in the earlier investigations and this Company was included in the domestic industry in certain cases and in certain other cases it was excluded in the factual matrix of those cases. It is now established position of the law and jurisprudence evolved in other investigating authorities that Article 4.1 of ADA and Rule 2(b) of Antidumping Rules do not provide for the automatic exclusion of producers which themselves import the dumped products, but rather obliges the Authority to examine on a case-by-case basis whether the inclusion or exclusion of any producer in such a situation is warranted. In deciding whether to exclude a domestic producer from the scope of the domestic industry, the Authorities generally examine the following factors:

- Whether the imports are sporadic and small compared to its own production and sales, not a regular phenomenon;
- Whether the imports are necessitated to tide over certain situations, say production issues; or supplementing the grades not manufactured by it; or quality testing and product development etc.;
- Need for completing their product range so as to be able to satisfy demand;
- Whether there is no other viable domestic producer to be defined as domestic industry.

20. The discretion available to the Authority under Rule 2 (b) has been used in the past with due circumspection in situations where the complaining producer is the only domestic producer or the imports are not very significant in comparison to their production and sale and/or imports are meant for product development and testing etc. In the instant case, SI Group has been importing the subject goods in significant quantities though it has been submitted that major portion of the goods are being imported for its downstream production for export sales. Further, a small quantity of the imports has been sold in the domestic market and this fact was not brought to the notice of the Authority at the time of initiation. However, the Authority notes that there is only one other domestic producer in the country in the public sector i.e., M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd.(HOCL) with significant production capacities. But the production facilities of HOCL has been on and off out of production and operated only for few months during the POI because of certain other factors though the domestic industry has argued that the production of this producer has been significantly affected by several factors, including prolonged dumping from various sources leading to closure of the plant for a considerable period during the POI. In this situation if SI Group is disallowed to be a part of the domestic industry for the purpose of injury examination, there will be practically no viable domestic industry to evaluate the injury and injury investigation will be significantly skewed or would not enable a reasonable analysis of the impact or likely impact of the imports from the subject countries.

21. In view of the above situation, the Authority is inclined to use the discretions available to it under Rule 2(b) with due circumspection and considers SI Group as a part of the domestic industry for injury examination in this case.

22. The opposing interested parties, in their post disclosure submission, have commented that the Authority has taken a step in the right direction by examining several factors in deciding whether to exclude a domestic producer from the scope of the domestic industry. However, In spite of analyzing the above factors, the Authority has decided to exercise its discretions available to it under Rule 2(b) with due

circumspection and has determined that SI Group constitutes Domestic Industry, simply because if SI Group is disallowed to be a part of the domestic industry for the purpose of injury examination, there will be practically no viable domestic industry to evaluate the injury and injury investigation will be significantly skewed or would not enable a reasonable analysis of the impact or likely impact of the imports from the subject countries. This might set a perilous precedent, whereby the Indian manufacturer will always find a way to qualify as domestic industry despite importing the subject goods and benefitting out of such imports. It has been further argued that the imports made by SI Group have had a substantial impact on the domestic market in India, even if they were mostly utilized for downstream exports. Further, SI Group has evidently benefited from these imports since it is able to competitively price its downstream product in the export market.

23. In this connection the Authority notes that all issues raised by the opposing interested parties have been examined and in the factual matrix of the case it was found necessary to retain SI Group as a part of the domestic industry for injury examination in this case.

E. Interested Parties to this investigation

24. Apart from the petitioners the responding exporters and importers who have made themselves known as interested parties in this investigation, as listed in para 5 (iv) and (vi) above, and the Governments of the responding countries have been treated as interested parties to this investigation.

F. Miscellaneous Submissions

F.1 Confidentiality

25. The opposing interested parties, in their submissions, have contended that petitioners have claimed excessive confidentiality. It has been argued that the domestic industry has not provided the basis for adjustments to export prices and Indexed ranges for costing information in Format A, B, C-1, C-2, D and E have not been provided and the underselling margin, capital employed and non-injurious price have not been disclosed in the petition in summarized form or in indexed ranges.
26. With regard to the confidentiality issues the domestic industry has submitted that all confidentiality claims of the domestic industry are as per the legal provisions, trade notice issued by the DGAD, and practice being followed by Authority in this regard. It has been further submitted that the questionnaire responses submitted by the interested parties are excessively confidential and prevent the domestic industry from making reasonable submissions.
27. The issues raised by the interested parties with regards to confidentiality have been examined. The Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties. As far as the submissions of the exporters are concerned, the information provided by the exporters, to the extent they are not business sensitive to the party providing the same, have been placed in the public file. In view of the above the objections of all parties with respect to confidentiality claims of the opposing parties have been disposed of.

F.2 Other Issues

28. The opposing interested parties have further argued that the Petition for sunset review filed by the Petitioners is deficient to the extent that it does not adequately address likelihood and provides baseless allegations without any evidence to corroborate its claims. In fact, as regards the claim of likelihood, the Petitioners appear to be contradicting themselves. The Petitioners have claimed in the petition that the performance of the domestic industry shows no improvement. In the same paragraph, the Petitioners have then stated that there is no injury to the domestic industry because dumping has continued at low level.

Such ambiguous statements are meant to mislead the interested parties and the Designated Authority. Therefore, the petition should be rejected.

29. Further the Petitioners have out rightly contradicted themselves on their own Petition as far as imports of the subject goods from Japan. The data indicates that there has been no import of the subject goods from Japan in the period of investigation and the previous year.
30. It has been submitted that Authority has, in several investigations, examined such a factual scenario, wherein there were no present imports from the subject countries in the recent years and revoked the duties in such cases. Therefore, given the fact that: (i) there are no imports of Acetone from Japan; (ii) there is sharp decline in imports of Acetone from Thailand and (iii) SI Group being major importer of Acetone during POI, there is no reason for continuing the anti-dumping duty in force on imports of the subject goods.
31. The exporters, in their submissions have also argued that the petitioners are inherently inefficient and have caused injury to themselves due to their operational infirmities and setbacks and resorting to repeatedly reliance on antidumping measures for over a decade. It has been argued that since its inception of its plant in 1987, HOCL has failed to make any improvement in its production facility or process even though the demand in the country has increased by nearly 200% since 1999. Since 2005 HOCL has been classified as a sick company and recently due to fall in international prices of crude Phenol manufacturing plant of HOCL has been shut down and HOCL has publicly admitted that these shutdowns are as a result of raw materials shortages which have no co-relation with the alleged dumping of the subject goods. Further, severe shortage of the working capital has also led to stoppage of production.
32. The domestic industry in its submissions has argued that the significance and purpose of imposition of anti-dumping duties is that the domestic industry gets increased fair market opportunities to sell its materials at fair prices. The domestic industry in the present case did not get fair market opportunity with the imposition of anti-dumping duty. However, cessation of anti-dumping duty would result in continuation or recurrence of duty and consequent injury to the domestic industry.
33. In their post disclosure submissions, the opposing interested parties have submitted that the merits of the present investigation can be adequately analysed only if due consideration is given to the history of the AD duties. The Authority has taken a due note of this fact in the disclosure statement. It has been argued that Anti- Dumping duties have been repeatedly relied on by the domestic industry for over a decade to buffer its own inefficiency and have attempted to systematically eliminate all competition from the domestic market.
34. The Authority notes that this product has a long history of anti-dumping investigations and duties have been imposed on the import of the subject goods from various countries since 2002. Apart from the subject countries, the duties are currently in force against imports from Chinese Taipei, USA, EU, Korea RP, South Africa, Saudi Arabia and Singapore.
35. With regard to the arguments of the interested parties that the petitioners are seeking repeated protection of antidumping duty while they are inherently inefficient, the Authority notes that in a sunset review investigation it is the consistent practice of the authority to review all the aspects of the original investigation, including the likelihood scenario of dumping and injury in the even to cessation of duties. Accordingly, all issues raised by the interested parties have been duly examined to the extent they are relevant and supported by evidence.

36. All other issues raised by the interested parties with regard to dumping and injury have been addressed in the respective sections in this finding to the extent they are relevant and supported by evidence.

G. Methodology of Determination of current Dumping

G.1 Legal Positions

37. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that: -

“The anti-dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

38. Accordingly, in a sunset review investigation the Authority is required to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti-dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.

39. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination as to whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, before examining whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of such dumped imports and injury is likely to continue or recur in such a situation.

G.2. Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

40. The Authority notes that the following producers and exporters from Thailand and Japan have submitted their questionnaire responses:

1. M/s PTT Phenol Company Limited, Thailand (Producer)
2. M/s MITSUI & CO., LTD., JAPAN, (Exporter)
3. M/s MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD., Singapore (Exporter)

41. The current dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods from these two countries have been examined based on the information filed by the cooperating exporters and other information provided by the domestic industry as follows:

Thailand

42. As per DGCI&S import data relied upon 3880 MT of Acetone was imported from Thailand during the POI. M/s PTT Phenol Company Limited, Thailand (PPCL), one of the major producers of the subject goods in Thailand has filed its questionnaire response in this case. As per the verified data of this exporter

they had exported [***] MTs of the subject goods to India during this period. The difference is apparently because of one transaction of previous period being cleared in the POI.

43. During the POI PPCL exported the subject goods to India directly to unrelated customers in India. The responses filed have been verified through on-spot investigations. Accordingly, the normal value, export price and dumping margin have been determined based on the verified data of the producing exporter as follows:

Normal Value

44. During the POI PPCL sold [***] KG of the subject goods in the domestic market. However, only [***] KG was produced and sold against [***] transactions while the balance was traded sales. The domestic sales are against contracts signed with the regular buyers and the prices are determined by formula linked to ICIS LOR South East Asia Price. During the POI PPCL sold the subject goods in the domestic market to unaffiliated customers. Domestic supplies are ex-tank or delivered with various credit/payment terms. The Company provided details of these expenses for adjustment to domestic sales prices.
45. It was noted that though the domestic sales were throughout the POI the export sales were only in certain months in the POI. Due to significant fluctuation in prices of basic raw materials, i.e. benzene and propylene, in the global market the producer has requested for determination of normal values and export prices on monthly basis and has provided month wise cost sheet of Acetone. Accordingly, the month wise domestic sales were subjected to ordinary course of trade test and the monthly normal values have been determined as follows after adjusting the domestic sales prices for expenses towards Inland Freight, Handling expenses and Credit Cost wherever applicable as given in the dumping margin table below.

Export Price

46. During the POI PPCL exported [***] KG of the subject goods directly to independent buyer in India. All sales were on FOB term and with 90 day's credit. The producing exporter has provided information on expenses towards handling expenses, which included storage cost, throughput cost, shipping cost and surveyor fee, and credit expenses which were verified.
47. Acetone is first delivered to Thai Tank Terminal for distribution, both for domestic and export in bulk. The Company pays a fixed fee and throughput fee to Thai Tank Terminal. Accordingly, PPCL has claimed handling expenses, which are comprised of storage and throughput expenditure. The net ex-works export prices of the company for its exports have been determined after due adjustments towards Inland freight, ocean freight, handling expenses, credit cost, bank charges, wherever applicable. The exports are in bulk form and no packing expenses are involved. Accordingly, month-wise net ex-works export prices work out as given in the dumping margin table below.

Dumping margin

48. The month-wise normal value determined at ex-works level have been compared with the month-wise export price to arrive at the dumping margin for PPCL as follows:

Row Labels	Sum of Quantity in Kgs	NV US\$/Kg	EP US\$/Kg	DM US\$/Kg	DM %
May-13	***	***	***	***	
Aug-13	***	***	***	***	
Nov-13	***	***	***	***	
Grand Total	***	***	***	***	5-15 %

All other exporters from Thailand

49. There is no other producer of the subject goods in Thailand. Therefore, determination of residual dumping margin for other producers and exporters in Thailand is infructuous and therefore, has not been carried out.

Japan

50. The DGCI&S data relied upon indicates that no imports of the subject goods has taken place from Japan during the POI. No questionnaire response has been filed by any producer of the subject goods in Japan. Therefore, no determination of dumping margin has been made in respect of Japan.
51. The above examination indicates that the dumping margin of the subject goods imported from Thailand during the POI was above *de minimis* level and there was no dumping from Japan during the said period.

H. Likelihood of continuation or recurrence of dumping**H.1 Views of the opposing interested parties**

52. The opposing interested parties, in their submissions have argued that
- i. Petitioners have calculated some vague and unsubstantiated dumping margins.
 - ii. Petitioners have not only not provided any evidence to substantiate export orientation; they have failed to give the source of third country data and evidence in this regard.
 - iii. The argument of price attractiveness is contradictory because the petitioner's data suggests that the present export price to India does not allow for recovery of cost. Petitioner's argument contradicts the concept of producer's equilibrium. They are posing selling below cost to be 'attractive'.
 - iv. Price undercutting has remained constant in the POI yet the extent of injury and profitability has seen radical variation implying that price undercutting has no correlation to the injury suffered by the domestic industry.

H.2 Views of the domestic industry

53. The domestic industry, in its submissions has argued
- i. That dumping has continued in case of Thailand. The volume of imports is significant enough in case of Thailand to allow a determination with regard to likelihood in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - ii. That in case of Japan, although there have been no imports during the present POI, the presence of, significant exports to third countries at dumped prices clearly shows likelihood of dumping and injury. Thus the dumping is likely to recur in case of cessation of anti-dumping duty.
 - iii. That there are significant exports from Japan to third countries revealing a significant injury margin. There is significant dumping in the third countries from Thailand as well. Therefore, in the event of cessation of the anti-dumping duties, there is strong likelihood of these third country imports getting dumped in India.

- iv. That Dumping Margin determined in previous investigations and present petition are significant and clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- v. That the prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market.
- vi. That there is significant price undercutting which is likely to intensify if the duties are revoked. Significant price undercutting by the Japanese exports is likely, considering the prices at which the Japanese exporters have exported the product under consideration to third countries in the POI.
- vii. That there is no contradiction in domestic industry's statements with regard to likelihood. Dumping of the product under consideration, injury to the domestic industry, injury to the domestic industry from present subject countries, injury to the domestic industry from other dumping sources, injury to the domestic industry from present subject countries in the event of cessation of anti-dumping duty are all different parameters and must be considered accordingly.
- viii. That excess capacity is a proved parameter to determine likelihood, it is sufficient to show high probability of injury to domestic industry.
- ix. That excess capacity in a country can lead to many problems in the home country such as falling product prices, deteriorating profitability, corporate –sector distress and financial sector distress which can cause the producer to look for avenues outside the country at disposable prices. The purchasing power of the citizens may not grow at the same rate. In such situations since the demand is already excessive, the investments are controlled because in such a scenario investments result in loss rather than profit. A glut of capacity is an important indicator of likelihood analysis in anti-dumping investigations.
- x. That it is not necessary that the price undercutting increases with increase in losses. The two are different parameters.

H.3 Examination by the Authority

- 54. It was noted in the previous section that there were no dumped imports from Japan during the POI. The imports from Thailand was at dumped prices. In view of the above what is required to be examined in this review is whether the dumping would continue from Thailand or recur from Japan if the duties are revoked. In this connection the Authority has looked at the price behavior and capacities of the major producers in the subject countries.
- 55. As far as Thailand is concerned, PPCL is the only major producer of Acetone in Thailand with a maximum capacity of about [***] KT per annum which they operate at above 100% capacity utilization. It has been submitted by the Company that the consumption of Acetone in Thailand is mainly for BPA and MMA production and annual demand is approximately 160,000 MTs. Since they have started their own Bis-Phenol A (BPA) production since 2010, their export of Acetone has substantially reduced. Export quantity has further reduced after they started MMA production in 2013. The data submitted by PPCL indicates that their domestic sales and captive consumption constitutes about ***% of their annual productions on annualized basis over the injury investigation period. The exports, which accounted for about ***% of production, has come down to about *** % in the POI indicating increased domestic consumption of the goods.

56. PPCL, in its response has indicated that they are considering to augment their capacity in the near future to double phenol capacity for the purpose of fulfilling major demand from domestic market and third countries. The Acetone capacity will also be increased in that proportion. The Company has indicated that the capacity is being augmented to cater to the demands from the domestic and third country customers. Therefore, while export orientation of the Company has been gradually diminishing with increased domestic consumption it appears that PPCL will still have significant export of the subject goods to various countries in the near future.
57. The Price trend of PPCL during the period of investigation indicates that the prices in the domestic market, and third countries were in a narrow band. The export prices at gross level are marginally higher than the domestic prices. Though the gross level prices may not clearly indicate the actual level of dumping, it would not be significantly high. Hence the arguments of the domestic industry that the third country exports from Thailand are at dumped prices and therefore, there is a likelihood of intensified dumping to India, if duties are revoked, do not seem to be supported by these facts. In this connection the post POI (Oct 2014-March 2015) data has also been examined and the data shows that there has not been any significant increase in volume of imports of Acetone from Thailand despite the fact that HOCL has gone completely out of production and the additional gap of about 20,000 MT has to be filled up through increased imports. On the price front the prices from across the countries show significant drop from the first quarter of 2015 apparently because of crude price situation. Therefore, it appears that the imports from Thailand would continue at the current level even if the duties are removed. Since the prices from Thailand is following the global trend, major reduction of prices by this producer vis a vis other global producers do not appear to be imminent.
58. As regards Japan, there is no import of Acetone from that country during the POI and also during the post POI period. During the injury investigation period there was significant import in 2011-12 and 2012-13. No response has been received from any producer in Japan. However, Mitsui & Co. a major exporter of the subject goods in Japan has filed a questionnaire response in which it has provided the production and domestic consumption data in Japan. As per this data Japan's total production of Acetone is about 375KTs, down from 500 KT in 2013, apparently because of closer of joint venture plant Mitsui Chemicals with Idemitsu at Kosan in September 2014. As per the above data the demand in the country, which was significantly below the production, would match up with the domestic production, indicating no significant excess production in the country.
59. The price level indicated by Mitsui & Co shows that at gross level domestic prices and prices to the third countries are in a narrow band. The Company has not exported the subject goods of Japan origin to India during the POI. There is no import from Japan in the post POI period either.
60. ICIS report on the demand supply scenario in Asia indicates that outside China, strained margins prompted producers in Asia region [to scale back](#) their phenol/acetone output in 2015. Demand growth for acetone is expected to again lag the supply gain in 2016. In the downstream sectors, there is limited expansion in [Bisphenol A](#) (BPA) and [Methyl Methacrylate](#) (MMA) capacities. The only notable BPA capacity increase in 2016 is the 110,000 tonne/year BPA expansion planned by Covestro at its Shanghai site. That will boost acetone consumption by 30,000 tonnes/year. Three new MMA plants, with a combined MMA capacity of 175,000 tonnes, are scheduled to start up in China in 2016, according to data compiled by ICIS China. At full operating rates, these are expected to consume 122,500 tonnes/year of acetone. In the first quarter of 2016, Jiangsu Sailboat Petrochemical is expected to commission its new 100,000 tonne/year MMA plant while Shandong Hongxu Chemical will complete the expansion of its MMA capacity by 25,000 tonne/year, according to data compiled by ICIS China. Construction of Dongming Huayi New Materials's new 50,000 tonne/year MMA plant is under way and the plant is due to

start up in late 2016. As per the ICIS report, deepening slowdown in Asia's largest economy is also likely to sap demand for acetone in the [solvents](#) sector, the biggest downstream segment accounting for 40-50% of acetone consumption in China. Fresh signs of further economic weaknesses in China – as evidenced by the most [recent manufacturing](#) and [producer price data](#) – indicates limited prospect for acetone demand growth. The report also indicates a significant drop in prices of Acetone, post Oct 2015, because of weak demand in China.

61. The overall assessment of demand supply and price scenario in Asia region indicates there could be some export of Acetone to India from Japan and Thailand if the duties are removed and the imports may follow the price trend as indicated in the ICIS report. Therefore, likelihood of continuation of dumping from Thailand and recurrence of dumping from Japan cannot be ruled out.

I. Methodology and Determination of Injury and Causal Link

62. As noted earlier, in a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.

63. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject countries. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

J. Determination of Injury and Causal Link

J.1 Submissions of the opposing interested parties

64. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- i. There is a contradiction in the petitioners' submissions that domestic industry performance shows no improvement and at the same time domestic industry claims that this is a case where dumping has continued at low level and the domestic industry has not suffered injury because of low level of dumping but injury to the domestic industry i.e. likely in case the present anti-dumping duties are withdrawn.
- ii. That as per market intelligence it is known that a large portion of the imports of the subject goods have been made in the injury period as well as the period of investigation under the advance license scheme. Under the said scheme, any domestic producers seeking to export his finished products may import their raw materials under the said advance license. The advantage of such a scheme would be that any imports made under advance license are exempted from any anti-dumping or safeguard duties. SI Group, one of the applicants in this case, has imported significant quantities of the subject goods under advance licence. Therefore, DA must segregate and analyze SI Group imports into duty paid and duty free imports and the same should be made available to the interested parties;
- iii. Citing the judgment in *Vetcare Organic Pvt. Ltd. vs CESTAT, Chennai*, 2011 (269) E.L.T. 444 (Mad.), and *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri. - Del.), the opposing interested parties have argued that imports under advance license ought to be identified and excluded from the import volumes considered for examining injury and dumping.

- iv. That any injury suffered by HOCL is inflicted by its own inefficiencies, operational infirmities and other setbacks and has been seeking protection of antidumping law for over a decade now which is evident from the plethora of investigation since 2002.
- v. That in a Safeguard investigation in 1999 HOCL submitted an adjustment plan in lieu of the safeguards duty in which they gave some exaggerated plans to expand capacity and minimise cost as they admitted then that one of the reasons identified by them is the lack of economies of scales. Despite that admitted fact and adjustment plans HOCL's capacity remains at the same exact level as it was in 1999.
- vi. That in the present petition HOCL has admitted that the long shutdowns are a result of raw material shortages, and other issues which have no correlation to the alleged dumping of the subject goods. Despite several help from parent ministry and various anti-dumping duties HOCL was classified as a sick company by BIFR under SICA and has remained so for nearly a decade. Reliance has been placed on the Ninth Report of Parliamentary Committee on Public Undertakings (2015-16) which clearly records that even after 16 years having elapsed from its proposal submitted to Directorate General of Safeguards, HOCL has not upgraded the technology for manufacture of Cumene by the use of modern zeolite catalyst system.
- vii. That this shows that there is indeed no injury due to the alleged dumping and the Petitioners are abusing the anti-dumping laws by misrepresenting before the Hon'ble Authority. Further, this reflects an inability to overcome HOCL's inefficiency and a lack of initiative to expand and seize the expanding demand.
- viii. That HOCL, has had repeated and sustained plant shutdowns in recent years, including the period of investigation. Since 2005, HOCL has been classified a sick company under the Indian law. Recently due to an international fall in crude prices, the Phenol manufacturing plant of HOCL was shut down again. These continuous shutdowns have impacted the ability of HOCL to supply to the domestic market and consequently HOCL's performance has suffered. In fact HOCL has publically admitted that these shutdowns are as a result of raw material shortages, which has no correlation to the alleged dumping of the subject goods.
- ix. That as admitted by HOCL, the Rasayani plant remains closed as of today and yet the Petitioners claim that their production and sales levels have been falling due to alleged dumping.
- x. That a severe shortage of working capital has also led to stoppage in production. The Company is on record in public domain that Kochi Refinery, which was supplying the raw materials, has refused to continue the supply as the Company had a debt of over 90 crores. Therefore, reintroduction of the anti-dumping duty will hardly help them to bring the plant to operation.
- xi. That there is a huge demand-supply gap in the country making imports inevitable.
- xii. That the injury to the domestic industry is not due to imports but due to various other factors as highlighted in the Parliamentary Committee Report such as high cost of production, huge demand-supply gap, poor technology, plant inefficiencies, plant shutdowns, lack of foresight and poor management.

- xiii. The production has suffered due to recurring and sustained plant shutdowns. The domestic industry has lost 22% market share while the subject countries imports have gained only 4% of the market share. The majority share is attributed to the imports from Korea and Singapore.
- xiv. The performance of SI Group, the only other producer of the subject goods in India has been much better, indicating internal inefficiencies of HOCL causing loss of market share.
- xv. That excess capacity of the exporters cannot be prejudiced against them. There is no proposition under any law or WTO that one must only produce what is required by it. The assumption that any excess capacity in the world will hit only India is faulty and hurts the consumers.
- xvi. That there is breach in causal link as no injury has been suffered on account of subject imports. There is heavy impact of imports from Korea and other countries not including subject countries. HOCL has acknowledged that it is the withdrawal of anti-dumping duties on other countries and not the subject countries, since the duties on subject countries were never ever removed.

J.2 Submissions by the domestic industry

65. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:
- i. That the demand for the product under consideration has increased in the POI with respect to the base year.
 - ii. That the volume of imports from Thailand in the POI were much higher than the imports in the base year and is significant enough to establish dumping and injury for the purpose of deciding the likely situation.
 - iii. As regards Japan, while there were no imports in the present period, Japan has exported significant volumes to third countries, which shows significant price undercutting, dumping margin and injury margin in the event of cessation of anti-dumping duty and diversion of these goods to India. There is strong likelihood that volume of imports shall increase further if anti-dumping duties are removed.
 - iv. In case of Thailand the subject imports are undercutting the prices of like product in India. However, in case of Japan third country exports are at such prices that cessation of anti-dumping duty shall result in diversion of goods to the Indian market and the domestic industry would suffer price undercutting.
 - v. Imports are undercutting the domestic price and effect of cessation of anti-dumping duty shall have significant suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
 - vi. While the current low volume of imports from Thailand and no imports from Japan was due to the anti-dumping duty in force and should the present anti-dumping duty be withdrawn, it is evident that the dumping would intensify and the imports from these countries shall cause injury to the domestic industry.
 - vii. Domestic industry has continued to suffer material injury due to continued dumping of the products in the country.
 - viii. The jurisprudence on the issue of advance licensing warrants that the import volume coming under advance licensing is causing a price injury. Therefore, it cannot be excluded.

- ix. The imports of SI Group are duty free imports made against export obligation and therefore, are not a cause of concern for the present investigation.
- x. There is no obligation on the Designated Authority to segregate and analyze SI Group imports into duty paid and duty free imports.
- xi. Demand supply gap justifies imports per se but not dumping of the product in the country. As held by CESTAT in the matter of DSM Idemitsu, if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market.
- xii. In past anti-dumping duties have only been imposed when the parameters are satisfied.
- xiii. The claimed injury is not due to developments in technology. Further it is an established principle that domestic industry should be seen as it is and not in the context of ideal conditions.
- xiv. Even if HOCL was classified as a sick industry an analysis must be done as to whether it was a sick company due to other reasons without attributing injury caused by other factors to dumping.
- xv. Raw material shortages are a result of prolonged dumping and consequent injury. There is a direct causal link
- xvi. Dumping leads to injury, leading to decline in profitability resulting in losses suffered by domestic industry, which impacts cash flow, which in turn affects the ability of the company to source raw materials. This leads to production suffering which adversely impacts the capacity utilization and sales. As a result, cost of production increases due to lower production and losses further impact the cash flow. The mounting cash flows impact the ability of company to source raw materials and this cycle continues so long as the market remains impacted by dumping.
- xvii. With regard to SI Group interested parties have focused on difference in performance whereas the requirement under the law is deterioration (or likelihood of deterioration) in performance.
- xviii. Injury to the domestic industry from other dumped imports does not imply "no injury or likelihood thereof" from present sources.
- xix. That the interested parties referred to reviews/recommendations of the Parliamentary Committee on public undertaking at the time of oral hearing and read extensively about the contents of its report, projecting as if the Parliamentary Committee has actually found entirely different reasons for adverse performance of HOCL and that HOCL has wrongly attributed their difficulties to the dumping in their product.
- xx. Despite anti-dumping duties in the past many years the domestic industry has been suffering from unfair competition from one source to another. This is primarily due to significant surplus in the global market and the ability of the global producers to dump the goods. The suspension of production by HOCL may turn to complete shut down if domestic industry is not meted out justified anti-dumping duties.

- xxi. If there is any mismanagement at the end of HOCL then it is rightly being dealt with by the parliamentary committee since HOCL is a public sector undertaking. Further for the purposes of anti-dumping the Authority would only recommend duty after following requirements prescribed under the laws. Such a finding of the Committee in no way jeopardizes the investigation process of Designated Authority.
- xxii. Contrary to the averment of the opposing interested parties the Committee recognized the 'negative' impact of the withdrawal of anti-dumping duty as one of the significant factors leading to dismal situation of HOCL.
- xxiii. That dumping has not just impacted HOCL, SI Group has also suffered. The Designated Authority may kindly examine the injury statements of the two companies.

J.3. Post disclosure submissions of the interested parties

- 66. In its post disclosure submissions, the domestic industry, has mostly reiterated its stand on the injury and causal link and had *inter alia* submitted as follows:
 - i. That the Price Undercutting is positive and is likely to increase the demand for the product under consideration in the market in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - ii. That HOCL suspended production because of intensified dumping of the product which has made its current operations totally unviable. HOCL has not completely gone out of business. It has merely suspended production. Which has been recommenced and a certificate as asked by the Authority was also provided
 - iii. That performance of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow has deteriorated. The information filed by SI Group clearly shows significant deterioration in its profits, cash flows and return on investment. While SI Group is a private enterprise, HOCL is a public sector organization. The financial losses being suffered by the company forced the company to reduce its production.
 - iv. That sales realization has been below cost of production in the period of investigation.
 - v. That because of dumping of the global surplus of the product in the Indian market, HOCL could not improve its performance further and is once again suffering losses.
 - vi. That the domestic industry is still suffering continued injury from the imports of dumped subject goods;
 - vii. That even at best capacity utilization, HOCL would have suffered significant adverse price effect in the POI.
 - viii. That none of the factors such as exchange volatility, inflation, high interest rates, and volatile stock markets are responsible for claimed injury to the domestic industry. There has been no significant change on any of these factors and as far as domestic industry and the present product is concerned. The performance of the domestic industry has, however, significantly deteriorated which clearly establishes that such deterioration is not because of the other factors.

- ix. That imports from Thailand are significant, which clearly shows that the Thailand producers are likely to cause significant injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty.
 - x. That HOCL has not adopted different methodology to allocate cost to Phenol and Acetone. HOCL has provided information in a consistent manner.
 - xi. That relevant parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and thereby establish causal link.
 - xii. That contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
 - xiii. That pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
 - xiv. That there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - xv. That technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are therefore, not a factor of injury.
 - xvi. That the fact of dumping is established by the Authority in all past cases. The significant global surplus in Phenol and Acetone capacity is clearly the cause of dumping of the product in India. Such significant surpluses are likely to continue. In fact, demand for Phenol is likely to increase without proportionate increase in demand of Acetone, which will further create pressure on Acetone prices in the global market.
67. The opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have argued as under:
- That if import volumes (or prices) prevalent in advance license imports are injuring a domestic industry, any levy of anti-dumping duties will not remedy such an injury. Unless there is a wide policy change, no levy of anti-dumping duties will be able to protect the Petitioners from advance license imports (whether dumped or not).
 - That imports might have been triggered due to the suspension of production by the domestic industry during the POI. Inflow of imports into India does not point towards dumping especially in the present case where the domestic industry has suspended production during the POI – in fact such competition is merely an indicator of a free market. Furthermore, as noted by the Authority at paragraph 71 of the Phenol disclosure statement, the major gain had been for the other non-subject countries attracting duties, and not subject countries. This aspect clearly indicates that there was no volume injury from the subject countries.
 - That the net sales realisation of the Domestic Industry still remains above the non-injurious price in spite of the fact that the cost and prices were affected due to suspension of the production by HOCL for a major part of the POI. This statement clearly indicates that there is a clear breach in causal link between imports from subject countries and the alleged injury claimed by the

Domestic Industry as the alleged dumped imports do not seem to restrict the Domestic Industry to recover its Non Injurious Price from the Indian market. Owing to this finding alone, the Authority should return a final finding recommending discontinuation of duties from the subject countries.

- That SI Group was in full production during the POI and was able to sell at a relatively higher price in the same market during the same period, much above the landed prices, which indicates that the dumped imports did not have suppression or depression effect on the domestic prices.
- That the HOCL shutdown was because of internal factors such as lack of modernization of technology, working capital crunch and non-supply of raw materials by the refinery due to mounting dues from HOCL and not because of alleged dumping from the subject countries.

J.4 Examination by the Authority

68. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties and the domestic industry on the injury and causal links and all the averments made have been examined taking into account the facts available on record and applicable law. Accordingly, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence injury on account of imports from the subject countries in the event of cessation of the duties.
69. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
70. For the purpose of current injury analysis, the Authority is required to examine the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability, to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.
71. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty was initially filed by HOCL and SI Industries and they have been treated as the domestic industry for the purpose of injury investigation in this review. However, as argued by the domestic industry performance of both the producers has also been examined separately, to the extent feasible, to see the state of health of both the domestic producers as HOCL was out of production for a considerable period during the POI thereby significantly affecting their performance indices.
72. The volume and price impacts of the dumped imports on the physical parameters of the domestic industry have been examined before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties.

A. Volume impact of dumped imports

(i) Import Volumes & share in Imports

73. The import data obtained from DGCI&S has been examined to analyse the trend in import volumes and prices and their impact on the domestic industry as follows:

Imports - (Volume)	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Subject Countries	MT	1,003	14,014	8,944	2,629	3,880
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>1,397</i>	<i>892</i>	<i>262</i>	<i>387</i>
Japan	MT	0	4,919	4,900	0	0
Thailand	MT	1,003	9,095	4,044	2,629	3,880
Countries Attracting ADD	MT	75,163	83,466	86,662	1,17,074	1,75,611
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>115</i>	<i>156</i>	<i>234</i>
Other Countries	MT	2,691	5,431	444	63	95
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>202</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Total	MT	78,857	1,02,911	96,050	1,19,767	1,79,586
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>122</i>	<i>152</i>	<i>228</i>

74. The data above shows that total imports during the injury investigation period grew almost by about 52% on annualised basis compared to the base year. However, while there is no import from Japan during major part of the injury period, including POI, imports from Thailand has increased significantly during this period by about 162% on annualised basis. But the imports from Thailand accounts for only about 2.2% of total imports. The Authority notes that though the subject goods are attracting antidumping duty on imports from several countries, imports from these countries have significantly increased during this period and account for about 97.75% of total imports, whereas imports from other countries are negligible.

75. The interested parties have argued that a significant volume of imports are under advance licence scheme without payment of the antidumping duties and therefore, the imports should be segregated and analysed for the injury analysis. However, none of the interested parties has provided any information on the volume of imports under advance licence.

ii) **Assessment of Demand and Market Shares**

76. The interested parties have argued that there is a huge demand supply gap in the domestic market. The demand data determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources is as follows:

Demand in India	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Sales of Domestic Industry	MT	48,442	39,897	37,539	26,566	39,849
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>77</i>	<i>55</i>	<i>82</i>
HOCL	MT	27,419	18,143	16,222	4,839	7,258
SI Group	MT	21,023	21,754	21,317	21,727	32,590
Dumped Imports from subject countries	MT	1,003	14,014	8,944	2,629	3,880

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>1,397</i>	<i>892</i>	<i>262</i>	<i>387</i>
Japan	MT	0	4,919	4,900	0	0
Thailand	MT	1,003	9,095	4,044	2,629	3,880
<i>Total Imports</i>	<i>MT</i>	<i>78,857</i>	<i>1,02,911</i>	<i>96,050</i>	<i>1,19,767</i>	<i>1,79,586</i>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>122</i>	<i>152</i>	<i>228</i>
Demand	MT	1,27,299	1,42,808	1,33,589	1,46,333	2,19,435
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>105</i>	<i>115</i>	<i>172</i>

77. The above data indicates that while demand has remained flat the imports have increased and domestic sales have declined significantly, particularly during the POI, largely because of decline in HOCL's sales. The trend in market share of various players in the domestic market during the POI was as follows:

Market Share in Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Sales of Domestic Producers	%	38%	28%	28%	18%	18%
HOCL (DI)	%	22%	13%	12%	3%	3%
SI Group	%	17%	15%	16%	15%	15%
Imports from subject countries	%	1%	10%	7%	2%	2%
Countries Attracting ADD	%	59%	58%	65%	80%	80%
Other Countries	%	2%	4%	0%	0%	0%
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

78. The above data indicates that the share of the domestic producers in the total demand has fallen largely due to production loss of HOCL as the other producer is producing at almost its full capacity and maintains its market share. The share of imports from Thailand has declined after increase in 2011-12 and 2012-13. But major gain has been for the other countries attracting duties, which corner about 80% of the market demand in the country.

B. Price impact of dumped imports

i) Trend of Import Prices

79. The import prices of the subject goods imported from various countries during the POI as per DGCI&S data is as follows:

Imports - (Prices)	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Subject Countries	<i>Rs/Kg</i>	<i>49</i>	<i>55</i>	<i>59</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
Japan	<i>Rs/Kg</i>		<i>55</i>	<i>58</i>		
Thailand	<i>Rs/Kg</i>	<i>49</i>	<i>54</i>	<i>60</i>	<i>68</i>	<i>68</i>
Countries Attracting ADD	<i>Rs/Kg</i>	<i>13</i>	<i>28</i>	<i>37</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
Other Countries	<i>Rs/Kg</i>	<i>43</i>	<i>56</i>	<i>70</i>	<i>81</i>	<i>81</i>
Total	<i>Rs/Kg</i>	<i>41</i>	<i>54</i>	<i>57</i>	<i>71</i>	<i>71</i>

80. The data above indicates that the CIF prices of imports from the subject countries are significantly high compared to other countries attracting duties. Import from other countries are insignificant in volume.

ii) **Price undercutting effect of dumped imports**

81. To examine the price undercutting effects of the dumped imports from the subject countries the landed values of the imports have been compared with the net sales realisations of the domestic industry.

Particulars	UOM	Thailand
Landed price of imports	Rs./MT	72,716
Net Sales Realization	Rs./MT	***
Price Undercutting (without ADD)	Rs./MT	***
	%	0-10%
Price Undercutting (with ADD)	Rs./MT	***
	%	0-10%

82. The data indicates that the dumped imports from Thailand undercut the selling prices of the domestic industry.

Price underselling effects of dumped imports

83. The landed value of the dumped imports has also been compared with the Non-injurious price determined for the domestic industry to see if the dumped imports had significant price underselling effect on the domestic prices.

Particulars	UOM	Japan	Thailand
Non Injurious Price	Rs./MT	***	***
Landed Price	Rs./MT	No imports	72,716
Price Underselling (without ADD)	Rs./MT		(***)
	%		(5-15)%
Price Underselling (without ADD)	Rs./MT		(***)
	%		(5-15)%

84. The above data indicates that the dumped imports did not have any underselling effect on the domestic industry's prices during the POI as the antidumping duty paid landed value of imports from the subject countries was above the non-injurious price of the domestic industry.

iii) **Price suppression or depression**

85. Since the cost of the domestic industry has been significantly affected by production loss and very low capacity utilisation during the POI, a reasonable analysis of the trends to see if the price of the domestic industry has been considerably suppressed because of the presence of dumped imports, is not possible. However, the trend of cost of sales, selling price and landed values of imports during the injury period are as follows:

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Cost of Sales	Indexed	100	152	193	226	226
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Selling Price	Indexed	100	131	137	159	159
Landed Price –subject countries (without duty)	Rs./MT	53,031	59,444	64,207	72,716	72,716
Landed Price –subject countries	Indexed	100	112	121	137	137

86. It is noted that the cost of the domestic industry has been significantly affected since 2012-13 because of significant drop in production of HOCL. However, trend of selling price has been higher than the landed values of imports from the subject countries. Therefore, it cannot be held that the prices are suppressed or depressed to any significant extent.

(i) Actual and potential impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

87. Considering the fact that the production the domestic industry (HOCL) was significantly affected during the POI, performance of both the domestic producer has also been examined separately in respect of sales, capacity, production and capacity utilization are as under, to see if the performance of both the producers was impacted by the dumped imports.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Capacity	MT	45,500	45,500	47,140	38,927	58,390
Trend	Indexed	100	100	104	86	128
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***
Production	MT	50,236	41,669	37,080	26,801	40,201
Trend	Indexed	100	83	74	53	80
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***
Capacity Utilisation	%	110.41%	91.58%	78.66%	68.85%	68.85%
Trend	Indexed	100	83	71	62	62
HOCL	%	***	***	***	***	***
SI	%	***	***	***	***	***
Domestic Sales	MT	48,442	39,897	37,539	26,566	39,849
Trend	Indexed	100	82	77	55	82
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***
Captive Sales	MT	2,825	1,163	622	327	490
Trend	Indexed	100	41	22	12	17
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	41	22	12	17

88. The Authority notes that while SI Group was operating almost at its full capacity during the entire injury investigation period HOCL's production has significantly declined since 2011-12. The Authority further notes that the production facility of HOCL was operational only for 119 days during the POI leading to this production loss and low capacity utilisation during the POI.
89. The interested parties have argued that the performance of the HOCL has been affected for a long time due to several internal factors. The petitioners on the other hand have argued that the performance has been affected because of presence of dumped imports from several sources. However, Authority notes that duties were in force on most of the major supplying countries, including the subject countries, during the entire injury period, except few producers from some of the countries. Moreover, near full capacity production of the other domestic producer does not appear to support this argument of the domestic industry, though certain fluctuation in international prices could have affected the production and capacity utilisation as is observed in the case of SI Group also.

(ii) Actual and potential impact on Profit/loss, return on investment and cash flow

90. The financial performance of HOCL during the injury investigation period for the subject goods as shown in table below.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	152	193	226	226
HOCL	Rs/MT	***	***	***	***	***
SI	Rs/MT	***	***	***	***	***
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	137	159	159
HOCL	Rs./MT	***	***	***	***	***
SI	Rs./MT	***	***	***	***	***
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	67	-32	-48	-48
HOCL	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
SI	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend		100	53	-24	-25	-37
HOCL	Rs.Lacs	***	***	(***)	(***)	(***)
SI	Rs.Lacs	***	***	(***)	***	***
Trend		100	73	-13	0	1

91. The Authority notes that the plant of HOCL was in operation for only 119 days out of 18 months of POI. Therefore, the cost is significantly affected by prolonged shutdown of the plant and would not reflect the true cost of production. The data of the previous year's show that HOCL was an efficient producer of the subject goods with higher profit margins compared to its domestic competitors till the time it was using its capacity fully. HOCL's capacity utilization started falling since 2011-12 leading to reduction in margins and subsequent losses in 2012-13 onwards. At the same time the other domestic producer continues to have a positive profit margin throughout except 2012-13 apparently due to increase in raw material cost. It is clear that the losses suffered by HOCL are on account of its inability to produce and sale during the period under consideration. Therefore, it is important to analyze the reasons for the production loss of HOCL during the injury investigation period.

92. Since one of the domestic producer, i.e., HOCL's plant was not operational for a prolonged period due to various reasons other mandatory parameters are irrelevant in this scenario.

K. Overall Assessment of Injury and Causal Link

93. Examination of the injury parameters as above indicates that one of the domestic industry, i.e., HOCL, has suffered significant production loss leading to financial losses. The previous section has established that there was no import from Japan. The imports from Thailand were at dumped prices. The other domestic producer continues to produce almost at full capacity and earn positive profit margins. Under these circumstances it is essential to examine whether the production loss and consequent financial losses suffered by HOCL was on account of dumped imports from the subject countries or because of other factors.
94. With regard to the production loss of HOCL and consequent injury in terms of financial losses the opposing interested parties, quoting the Parliamentary Committee Reports and other publicly available information, have argued that the production unit of HOCL has been shut down because of its internal inefficiencies and management problems rather than dumping. It has been submitted that inability of the unit to modernize and scale up to economic size and working capital unavailability has led to shutdown of the plant and not because of the imports from the subject countries.
95. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that HOCL suspended its production during the POI as the production and sales were unviable due to dumped imports and the plant has not been completely shut down. It has further been submitted that HOCL has resumed its production recently with certain arrangements of raw material supply from the Cochin refinery.
96. The Authority notes that the production unit of HOCL was set up in late 1980s with a capacity of about 40,000 MTs of Phenol and 45,000 MTs of Acetone and other ancillary products with raw material linkage with Cochin Refinery. The capacity and technology was perhaps based on the demand scenario and technology available at that point of time. Thereafter, the demand has increased significantly and technology has also improved, as noted by the Parliamentary Committee in its reports and submissions of the Company before other Authorities. But the Company has not been able to scale up the capacity or modernize the plant due to various reasons. The inability of the plant to scale up and modernize, coupled with dumping from several countries affected the performance of the Company and antidumping duties were imposed on imports of Phenol and Acetone from several countries starting in the year 2002. However, due to continued losses HOCL was declared a sick unit in 2005 and still continues to be under BIFR.
97. The Rashayani unit of the Company engaged in several other products with a significant workforce has been shut down since 2013. The Cochi Unit, which produced Phenol and Acetone with certain other products, was however, producing with full capacity for certain period before this also got affected by working capital problems as the profits of this unit was supporting the fixed expenses of the other unit closed earlier. Due to mounting dues of over 90 Crores to Cochin Refinery, against supply of raw materials, the Refinery has stopped raw material supply to the unit leading to suspension of production of the Cochi plant since Mid-2015.
98. The Authority further notes that imports from all major sources were attracting antidumping duties, except certain sources which were found not to be dumping in the respective investigations. Therefore, those imports cannot be attributed to the injury suffered by this producer.
99. The interested parties have also raised the issue of lack of modernization and adoption of efficient production methods and scaling up of the capacities to economic size as noted in various reports and its commitments to other Authorities as one of the causes of the injury. The Authority notes that the production facilities of the Company are old and has not gone through major modernization due to various factors, including dumping from several sources.

100. Therefore, overall assessment of the state of affairs of HOCL indicates that the closure of the plant is directly linked to its working capital and management issues rather than the dumped imports from the subject countries as antidumping duty protection was available against these imports for the entire injury investigation period. In view of the above the performance of the Company during the POI cannot be attributed to the imports from the subject countries. The very fact that HOCL has attempted resumption of production with certain agreements for raw material supply with Cochin Refinery further indicates that the suspension of production was due to raw material and working capital related issues and not significantly because of dumped imports from the subject countries.
101. The performance of the other domestic producer i.e., SI Group does not show any significant deterioration. Their production, capacity utilization and sales remain stable and the profitability remains closer to their 2011-12 level. Therefore, performance of this company does not appear to be significantly affected during this period though substantial imports are taking place from several countries at similar price bands.
102. Therefore, the Authority does not find any significant causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered by the domestic industry as a whole.

L. Magnitude of Injury and injury margin

103. Since the injury to the domestic industry is not found to be on account of the dumped imports from the subject countries determination of the injury margin is irrelevant. However, as per the Non-injurious price determined for the domestic industry on the basis of the relevant provisions of the Rules and taking into account the production loss during the POI, and the landed value of imports from the subject countries, the injury margins of imports work out as under:

Particulars	UOM	Japan	Thailand
Non Injurious Price	Rs./MT	****	****
Landed Price	Rs./MT	No imports	72,716
Injury Margin	Rs./MT		(****)
	%		(5-15)%

104. The landed value of imports is above the non-injurious price of the domestic industry indicating negative injury margin during the period of investigation.
105. The domestic industry has raised certain issues regarding the determination of the non-injurious price. However, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the consistent practice of the Authority in terms of the methodology in Annexure III of the AD Rules and taking into account the information provided by the domestic industry and therefore, no revision of the NIP is called for.

M. Likelihood of continuation of injury

106. The domestic industry has argued that the current price undercutting and/or the potential undercutting, based on third country exports from the subject countries would indicate that the goods will cause material injury to the domestic industry if the duties are revoked. The opposing interested parties have, on the other hand, argued that the injury has not been caused by the imports from the subject

countries and the domestic industry is suffering on account of its internal problems. It has been argued that there is no likelihood of recurrence of dumping from the subject countries due to prior commitment of major suppliers in the subject countries for their own captive consumption and other committed buyers.

107. In its post disclosure comments the domestic industry has reiterated its stand and has argued that in case of expiry of existing duty, exporters from the subject country would further channelize their output in the Indian market, as they are already holding excessive capacities and are highly export oriented. In fact, as acknowledged in the disclosure statement, producers in Thailand are increasing its capacity. This excessive capacity would be used to increase its exports and India being large demand would be first choice for them. The imports are still continuing at dumping prices rather increased in post POI. Thus, existence of such a situation after imposition of anti-dumping duty gives a clear implication of likelihood of injury.
108. The opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have argued that the post POI data does not indicate any significant increase in volume of imports from Thailand while import from Japan continues to be nil, though there is a significant demand supply gap arising out of closure of the plant of the domestic industry. The price level of imports from all sources shows a decline in prices because of the decline in raw material prices. It has been further argued that there is no likelihood of recurrence of dumping and resultant injury from Thailand due to prior commitment to buyers' major markets in third countries as well as for its own captive consumption.
109. As noted earlier there was no dumping of the subject goods from Japan during the POI. Dumping has continued from Thailand but at very low volumes during injury investigation period. It was also noted that there is no imminent likelihood of intensified dumping from the subject countries, keeping in view the capacities and demand supply position of the major producers in those countries. The post POI data does not indicate any significant increase in volume of imports from Thailand while import from Japan continues to be nil though there is a significant demand supply gap arising out of closure of the plant of the domestic industry. The price level of imports from all sources show a decline in prices apparently because of the decline in raw material prices. ICIS report confirms that there is a significant drop in price of Acetone across all countries in Asia region post Oct 2015. Therefore, the import prices from the subject countries do not show any abnormal price behaviour to indicate intensified dumping in the post POI period.
110. Post POI data (Oct-March 2015) of the domestic productions shows that the domestic industry was out of production for the entire period but the other producer continued to operate at almost full capacity. Further the analysis in the previous section establishes that the production of HOCL has been suspended largely because of its internal problems arising out of non-availability of working capital to purchase raw materials and outstanding dues to its raw material supplier. Therefore, the question arises whether the Company would be in a position to revive its production if the duties are continued.
111. The examination of various factors and information available with the Authority indicates that without resolving the working capital and management issues the unit would not be in a position to revive production and sale, even if an antidumping duty protection is provided against the subject countries. The resumption of production, with certain understanding with the raw material supplier recently, is yet to stabilise. Further the imports from other sources are at lower prices even after imposition of duties. Therefore, in the factual matrix of the case the Authority is of the view that though the injury to the industry is likely to continue it would not be on account of the dumped imports from the subject countries and continuation of the measure would be of no help in revival of the unit unless other measures are put in place.

N. Indian Industry's interest and other issues

112. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian domestic market. However, in the instant case one of the domestic producers have gone out of production because of factors other than dumped imports from the countries against which this review was conducted. The other domestic producer is not significantly affected during the period under review. There is significant demand supply gap in the domestic market which necessitates imports. Therefore, neither the interests of the domestic producers of the subject goods, nor the interests of the user industry would be best served if the duties on the subject goods from the subject countries are extended by another period of five years.

O. Conclusion and Recommendations

113. The Authority initiated and conducted this review investigation in accordance with the Law and examined the current dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty. It has been clearly established in the foregoing paragraphs that there was no dumping of the subject goods from Japan during the period under review. Dumping continued from Thailand but at a very low level. It was also found that though imports from Thailand may continue at the present level and some imports may take place from Japan, if the duties are revoked, there is no imminent likelihood of recurrence of intensified dumping of the subject goods from the subject countries. It has also been established that though one the domestic producer suffered injury during the period of review, the injury suffered is on account factors other than the dumped imports from the subject countries. The performance of the other domestic producer is not significantly affected during the period of review and decline, if any, cannot be attributed to the dumped imports as imports are taking place from other countries as well at similar price levels.
114. The examination also indicates that even if the duties are extended HOCL would not be able to revive its production to a level where it will be viable, unless other fundamental issues affecting the Company are addressed. Since one of the two domestic producers is out of production it has added to the demand supply gap in the country. Therefore, neither the interests of the domestic producers of the subject goods, nor the interests of the user industry would be best served if the duties on the subject goods from the subject countries are extended for a further period of five years.
115. Considering all the above, the Authority is of the view that there is no need for continued imposition of the duties on the import of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the Authority does not recommend continuation of definitive anti-dumping duties on import of Acetone, originating in or exported from Japan and Thailand, imposed vide Customs Notification No. 36/2011-Customs, dated 18th April, 2011.
116. Appeal against the orders of the Central Government that may arise out of the recommendations of the Designated Authority lies before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority